RNI No. MPHIN/2015/64451 डाक पंजीयन क्र. MP/IDC/1525/2022-2024 IPT डाक द्वारा प्रेषण प्रति शुक्रवार indianplasttimes@gmail.com
DPR No. N-193
www.Indianplasttimes.in

इंडियन प्लास्ट टाइम्स

■ INDORE ■ 06 DECEMDER TO 12 DECEMDER 2023 ■ प्रति बुधवार ■ वर्ष 09 ■ अंक 11 ■ पृष्ठ 8 ■ कीमत 5 रु.

Inside News

रूसी तेल पर कसा शिकंजा तो इस देश से सस्ता तेल खरीदने लगा भारत, हो रहा फायदा Page 2

अर्थव्यवस्था की तूफानी तेजी के साथ आज आई एक और गुड न्यूज Page 3

दूसरे सप्ताह भी विदेशी मुद्रा भंडार में भारी बढ़ोतरी Page 4

editoria!

इकॉनमी की रफ्तार

मौजूदा वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही (जुलाई से सितंबर) में उअ्र ग्रोथ की बढ़ी हुई रफ्तार ने सबको चौंका दिया। किसी ने नहीं सोचा था कि इकॉनमी इस अवधि में 7.6 फीसदी की रफ्तार हासिल करेगी। रिजर्व बैंक का भी अनुमान 6.5 फीसदी की बढ़ोतरी का था। इस आंकड़े से जुड़े कुछ खास पहलू ध्यान देने लायक हैं। पहला, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर 13.9 फीसदी बढ़कर 7.15 लाख करोड़ रुपये तक जा पहुंचा है। दूसरा, कंस्ट्रक्शन क्षेत्र 13 फीसदी इजाफे के साथ 3.04 लाख करोड़ का हो गया है। तीसरा, निवेश में 11 फीसदी की बढ़त हुई है, जिसके बाद यह 14.71 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। हालांकि इन चमकते बिंदुओं के साथ ही ग्रोथ के आंकड़ों से जुड़े कुछ ऐसे भी पहलू हैं, जो राह में आगे खड़ी चुनौतियों की ओर संकेत करते हैं। एक बात तो यही है कि प्राइवेट खपत में बढ़ोतरी की रफ्तार काफी धीमी रही है। इस दौरान इसमें महज 3.1 फीसदी की बढ़ोतरी हुई, जो आमदनी के वितरण के लिहाज से अच्छी खबर नहीं कही जा सकती। यह बड़ी बात है क्योंकि देश के उअ्र में खपत की भागीदारी 60 फीसदी है। इसके अलावा एक अहम मसला है कृषि क्षेत्र का कमजोर प्रदर्शन। पहली तिमाही में 3.5 फीसदी की रफ्तार दिखाने वाला कृषि क्षेत्र दूसरी तिमाही में 1.2 फीसदी की बढ़ोतरी ही दर्ज करा सका। सबसे बड़ी बात यह है कि साल के अगले हिस्से में भी इस क्षेत्र में बढ़ोतरी की अच्छी संभावना नहीं दिख रही, जिसका असर ग्रामीण क्षेत्र की मांग पर पड़ सकता है। मगर इन चुनौतियों के बावजूद देश की इकॉनमी पूरी दुनिया की उम्मीद का आधार बनी हुई है। उसके पीछे एक बडा फैक्टर है टैक्स कलेक्शन के मजबूत आंकड़े। ध्यान देने की बात यह भी है कि पिछले तीन वर्षों में भारत सरकार ने वित्त घाटे में राजस्व घाटे का हिस्सा कम कर लिया है। सीधे शब्दों में इसका मतलब यह है कि कर्ज का बड़ा हिस्सा निवेश में लग रहा है। इसके अलावा घरेलू बचत के स्वरूप में भी बदलाव देखा जा रहा है। पिछले तीन वर्षों में म्युचुअल फंड में निवेश तेजी से बढ़ा है। खासकर 2021-22 में इसमें ढाई गुना बढ़ोतरी देखी गई और उसके अगले साल यानी 2022-23 में 12 फीसदी की वृद्धि हुई। साफ है कि भारतीय अर्थव्यवस्था अगर दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई इकॉनमी है और इसे वैश्विक तौर पर ब्राइट स्पॉट माना जा रहा है तो यह स्थिति तुरंत बदलने वाली नहीं है। रिजर्व बैंक सालाना GDP के अनुमान में बदलाव लाता है या नहीं, यह देखना होगा। लेकिन कई स्वतंत्र विश्लेषक ऐसे संशोधित अनुमान पेश कर चुके हैं। मसलन, बार्कलेज ने इसे 6.3 से बदलकर 6.7 कर दिया है। मगर 6.3 फीसदी की अनुमानित विकास दर के साथ भी भारत घ्श्इ के अक्टूबर में जारी वर्ल्ड इकॉनमिक आउटलुक प्रोजेक्शन में सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में शामिल था। जाहिर है, कोई अप्रत्याशित उतार-चढ़ाव नहीं हुआ तो भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया की उम्मीद बनी रहेगी।

इंडिया की जीडीपी सिर्फ ढाई साल में जर्मनी से ज्यादा हो जाएगी

तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा भारत

नई दिल्ली। एजेंसी

इंडिया की जीडीपी दूसरी तिमाही में करेंट प्राइसेज पर 71.66 लाख करोड़ रुपये रही। इससे देश में प्रति व्यक्ति सालाना आय बढ़कर 2.01 लाख रुपये हो गई। डॉलर में यह सालाना करीब 2,436 डॉलर है। इस वित्त वर्ष (2023-24) की पहली छमाही में इकोनॉमी की ग्रोथ 7.7 फीसदी रही। अगर जीडीपी में यह ग्रोथ आगे भी जारी रहती है तो सितंबर 2030 तक देश में प्रति व्यक्ति आय बढ़कर 3,600 डॉलर सालाना पहुंच हो सकती है।

इस वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में जीडीपी की ग्रोथ (उअ्र उदैप्) 7.6 फीसदी रही। यह पिछले वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही की 6.2 फीसदी ग्रोथ के मुकाबले काफी ज्यादा है। इंडिया की जीडीपी दूसरी तिमाही में करेंट प्राइसेज पर 71.66 लाख करोड़ रुपये रही। इससे देश में प्रति व्यक्ति सालाना आय बढ़कर 2.01 लाख रुपये हो गई। डॉलर में यह सालाना करीब 2,436 डॉलर है। इस वित्त वर्ष (2023-24) की पहली छमाही में इकोनॉमी की ग्रोथ 7.7 फीसदी रही। अगर जीडीपी में यह ग्रोथ आगे भी जारी रहती है तो सितंबर 2030 तक देश में प्रति व्यक्ति आय बढ़कर 3,600 डॉलर सालाना पहुंच सकती है। 2014 में प्रति व्यक्ति आय मुश्किल से 1,560 डॉलर सालाना थी। दूसरी तिमाही में जीडीपी ग्रोथ में सभी सेक्टर का योगदान रहा। लेकिन, सबसे ज्यादा योगदान मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का रहा। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ 13.3 फीसदी रही।

इन सेक्टर का ज्यादा योगदान

कंस्ट्रक्शन दूसरा सबसे ज्यादा कंट्रिब्यूशन वाला सेक्टर रहा। इसकी ग्रोथ 13.3 फीसदी रही। इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई और दूसरी यूटिलिटी सर्विसेज की ग्रोथ 10.1 फीसदी रही। माइनिंग ने 10 फीसदी ग्रोथ के साथ जीडीपी में कंट्रिब्यूट किया। सर्विस सेक्टर की ग्रोथ बहुत अच्छी नहीं रही। एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ चिंताजनक रही। इस सेक्टर की ग्रोथ सिर्फ 1.2 फीसदी रही। लेकिन, इसकी कोई बुनियादी वजह नहीं है। मानसून की अपर्याप्त बारिश की वजह से कृषि क्षेत्र का प्रदर्शन कमजोर रहा।

आत्मनिर्भर भारत पॉलिसी का असर

मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ से केंद्र सरकार की आत्मनिर्भर भारत पॉलिसी की सफलता का संकेत मिलता है। हर सेक्टर में नई प्रोडक्शन यूनिट्स आ रही हैं। इनमें इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकॉम, मशीनरी, सोलर इक्विपमेंट, डिफेंस इक्विपमेंट, केमिकल्स, खिलौने, टेक्सटाइल्स आदि शामिल हैं। प्रोडक्शन-लिंक्ड इनसेंटिव (इथ्ध्) पॉलिसी के तहत जल्द लैपटॉप और सेमीकंडक्टर्स का उत्पादन शुरू हो गया है।

आर्थिक गतिविधियों तेजी से बढ़ने के संकेत

कोल, स्टील, सीमेंट, माइनिंग और पावर जेनरेशन में अच्छी ग्रोथ दिखी। कोल प्रोडक्शन की ग्रोथ 16.3 फीसदी रही। सीमेंट उत्पादन की ग्रोथ 10.2 फीसदी रही। स्टील प्रोडक्शन 19.5 फीसदी बढ़ा। माइनिंग की 11.5 फीसदी ग्रोथ भी उल्लेखनीय है। हवाई यात्रियों की संख्या 22.7 फीसदी बढ़ी। बैंक में डिपॉजिट 11.5 फीसदी बढ़ा। बैंकों के लोन डिस्बर्सल में 13 फीसदी ग्रोथ रही। इन सभी डेटा से पता चलता है कि देश में आर्थिक वातावरण बेहतर हो रहा है। यह समझने की जरूरत है कि मैन्युफैक्चरिंग में ग्रोथ का सीधा संबंध नौकरियों के नए मौकों से है। इसमें कोई संदेह नहीं कि मैन्युफैक्चरिंग में नौकरियों के मौके सर्विस सेक्टर के मुकाबले बहुत ज्यादा हैं।

जर्मनी से आगे निकल जाएगा भारत

जुलाई-सितंबर के दौरान जीडीपी की ग्रोथ 7.6 फीसदी रही। चीन में ग्रोथ सिर्फ 4.9 फीसदी रही। रूस में 5.5 फीसदी रही। अमेरिका में 5.2 फीसदी रही। जर्मनी अभी जीडीपी के मामले में इंडिया से दो पायदान आगे है। जर्मनी की जीडीपी 0.4 फीसदी घटी। ऐसी स्थिति में अगर इंडिया की वर्तमान ग्रोथ आगे जारी रहती है तो इस फाइनेंशियल ईयर के अंत में इसकी जीडीपी 3.5 ट्रिलियन (लाख करोड़) डॉलर तक पहुंच जाएगी। अगर जर्मनी की 4.1 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी में 0.4 फीसदी गिरावट आती है तो उसकी जीडीपी घटकर 4.08 ट्रिलियर डॉलर रह जाएगी। तब इंडिया की जीडीपी जर्मनी से सिर्फ 600 अरब डॉलर कम रह जाएगी। अगर इंडिया की यह ग्रोथ आगे जारी रहती है तो अगले ढाई साल में इंडिया की जीडीपी जर्मनी की जीडीपी से ज्यादा हो जाएगी।

देश में औंधें मुंह गिरी डीजल की बिक्री, 7 फीसदी से ज्यादा आई गिरावट

नई दिल्ली। एजेंसी

देश में डीजल की बिक्री में गिरावट आई है। रिपोर्ट के मुताबिक, नवंबर महीने में डीजल की खपत 7.5 प्रतिशत घट गयी है। इसकी वजह दिवाली पर ट्रक चालकों के अवकाश लेने से परिवहन क्षेत्र की मांग घटने के चलते डीजल की खपत कम हुई है। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के शुरुआती आकंड़ों से यह जानकारी मिली है। नवंबर में डीजल की खपत एक साल पहले के 73.3 लाख टन से घटकर 67.8 लाख टन रह गई है। उद्योग के अधिकारियों ने कहा कि ऐसा इसलिए है क्योंकि कुछ ट्रक चालक अपने घर जाने के लिए दिवाली में छुट्टी लेते हैं। दिसंबर में मांग काफी हद तक पिछले स्तर पर पहुंच जाएगी।

होती है सबसे ज्यादा खपत

डीजल भारत में सबसे अधिक खपत वाला ईंधन है। इसकी सभी पेट्रोलियम उत्पादों की खपत में लगभग 40 प्रतिशत हिस्सेदारी है। देश में कुल डीजल बिक्री में परिवहन क्षेत्र की हिस्सेदारी 70 प्रतिशत है। त्योहारों के दौरान निजी वाहनों की आवाजाही बढ़ने से तीन सरकारी ईंधन खुदरा विक्रेताओं की पेट्रोल बिक्री 7.5 प्रतिशत बढ़कर 28.6 लाख टन हो गई।

अक्टूबर में भी घटी थी बिक्री

अक्टूबर के पहले पखवाड़े में पेट्रोल की मांग सालाना आधार पर नौ प्रतिशत

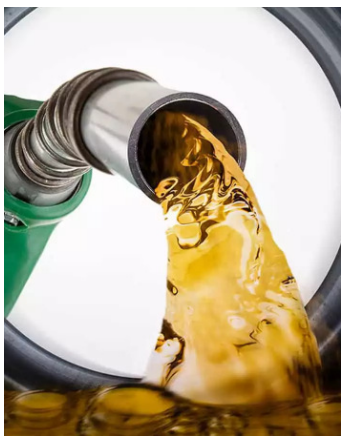

और डीजल की बिक्री 3.2 प्रतिशत गिर गई थी। नवरात्रि/दुर्गा पूजा उत्सव की शुरुआत से इस रुझान में बदलाव आया। नवंबर के पहले पखवाड़े में डीजल मांग में 12.1 प्रतिशत की कमी आई। हालांकि दूसरे पखवाड़े में इसमें कुछ सुधार आया।

इतने फीसदी हुई बिक्री

मासिक आधार पर डीजल बिक्री अक्टूबर में 65 लाख टन के मुकाबले नवंबर में 3.6 प्रतिशत अधिक रही। नवंबर में विमान ईंधन (एटीएफ) की बिक्री सालाना आधार पर 6.1 फीसदी बढ़कर 620,000 टन हो गई। हालांकि, यह आंकड़ा नवंबर 2019 की तुलना में 7.5 प्रतिशत कम है। नवंबर में रसोई गैस एलपीजी की बिक्री सालाना आधार पर 0.9 फीसदी घटकर 25.7 लाख टन रही।

रूसी तेल पर कसा शिकंजा तो इस देश से सस्ता तेल खरीदने लगा भारत, हो रहा फायदा

नई दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

रूस भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है लेकिन अमेरिकी प्रतिबंधों की सख्ती के कारण रूस से तेल खरीद में कुछ दिक्कतें आ रही है। रूसी तेल पर सख्त होते अमेरिकी प्रतिबंधों के बीच खबर आई है कि भारत ने एक बार फिर वेनेजुएला से तेल की खरीद शुरू कर दी है। मामले की जानकारी रखने वाले सूत्रों ने बताया है कि भारतीय रिफाइनरी कंपनियां बिचौलियों के माध्यम से वेनेजुएला से तेल खरीद रही हैं। इसी हफ्ते रिलायंस रिफाइनरी के अधिकारी वेनेजुएला की सरकारी तेल कंपनी इञ्र्रीं के अधिकारियों से मिलने वाले हैं। खबर है कि वेनेजुएला भारत को बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड से सस्ते दाम पर अपना तेल बेच रहा है।

अक्टूबर के महीने में अमेरिका ने वेनेजुएला के तेल आयात पर लगे प्रतिबंध को अस्थायी रूप से हटा दिया था। इसके बाद से ही तेल उत्पादक देशों ओपेक के सदस्य वेनेजुएला कई देशों को अपना तेल बेच रहा है। वेनेजुएला बिचौलियों और व्यापारियों के माध्यम से भारी मात्रा में दूसरे देशों को अपना तेल बेच रहा है, खासकर चीन को। प्रतिबंधों के हटने के बाद वेनेजुएला का पास अपने तेल को बेचने का बड़ा अवसर है लेकिन उसका तेल उत्पादन अस्थिर रहा है जिससे वो चाहकर भी ज्यादा तेल नहीं बेच सकता है।

भारत ने आखिरी बार 2020 में वेनेजुएला से कच्चे तेल का आयात किया था। वेनेजुएला से तेल की खरीद भारत के लिए फायदे का सौदा है। भारत फिलहाल सबसे अधिक कच्चा तेल रूस से खरीद रहा है जिसकी आयात लागत काफी ज्यादा है। रूस ने अब अपने तेल पर भारत को दी जानेवाली छूट भी कम कर दी है जिससे भारतीय रिफाइनरों को ज्यादा लाभ नहीं हो रहा है।

भारत और रूस के बीच दूरी अधिक होने से भारत को रूसी तेल का शिपिंग चार्ज काफी ज्यादा देना पड़ता है लेकिन वेनेजुएला से तेल खरीद की लागत सीमित है जो भारत के लिए फायदेमंद है। इसके साथ ही रूसी तेल पर अमेरिकी प्रतिबंध सख्त होते जा रहे हैं जिस कारण रूस से तेल खरीद में मुश्किलें आ रही हैं।

वेनेजुएला से कच्चा तेल खरीद की जानकारी रखने वाले पांच व्यापार सूत्रों ने समाचार एजेंसी रॉयटर्स को बताया है कि तीन भारतीय रिफाइनरों ने डिलीवरी एक्स-शिप के आधार पर कच्चे तेल के वैश्विक मानक ब्रेंट से 7.50 डॉलर और 8 डॉलर प्रति बैरल कम कीमत पर वेनेजुएला से लगभग 40 लाख बैरल कच्चा तेल खरीदा है। इस तेल की डिलीवरी फरवरी में होने वाली है। 40 लाख बैरल की इस तेल खरीद में ट्रेडिंग हाउस न्यूदत शामिल रहा है जिसने वेनेजुएला का 15 लाख बैरल तेल इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन और पांच लाख बैरल प्ज्ञ्थ-मित्तल एनर्जी को बेचा है।

एक अन्य सूत्र ने बताया कि रिलायंस को पहले फ्री-ऑन-बोर्ड आधार पर ब्रेंट से 16 डॉलर प्रति बैरल कम कीमत पर तेल का प्रस्ताव मिला था लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि यह डील हुई या नहीं। वेनेजुएला के उप तेल मंत्री ने पिछले महीने कहा था कि उनका देश लगभग 850,000 बैरल प्रति दिन कच्चे तेल का उत्पादन कर रहा है, जिसे जल्द ही 10 लाख बैरल प्रतिदिन तक पहुंचाने का लक्ष्य है। वेनेजुएला बार-बार 10 लाख बैरल प्रतिदिन तेल उत्पादन का लक्ष्य तय करता है लेकिन वो बार-बार इससे चूक जाता है।

एक वक्त रिलायंस वेनेजुएला की सरकारी तेल कंपनी इञ्र्रीं का दूसरा सबसे बड़ा कच्चा तेल खरीददार था। बदले में वो वेनेजुएला को भारी मात्रा में ईंधन का आपूर्ति करता था। एक सूत्र ने बताया, 'रिलायंस की टीम ने पहले ही कराकस (वेनेजुएला की राजधानी) में इञ्र्रीं के अधिकारियों के साथ बैठकें निर्धारित कर ली हैं। उम्मीद है कि चर्चा में भारत को कच्चे तेल की बिक्री और वेनेजुएला के लिए ईंधन आयात शामिल हो सकता है।

वेनेजुएला से कितना तेल भारत आ चुका है?

अभी तक वेनेजुएला से तेल का एक भी कार्गो भारत नहीं पहुंचा है, लेकिन नवंबर के अंत में वेनेजुएला के कुछ जहाजों में भारत के लिए तेल की लोडिंग हो गई है। टैंकर ट्रैकिंग डेटा और शिपिंग शेड्यूल के अनुसार, तेल टैंकरों को दिसंबर में भारत के लिए वेनेजुएला से रवाना किया जा सकता है।

रूस से तेल खरीद में बाधा के बीच वेनेजुएला ने जगाई उम्मीद

कुछ दिनों पहले ब्लूमबर्ग ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा था कि कच्चे तेल से भरा रूस का एक टैंकर भारत के तट के पास पिछले कई दिनों से भटक रहा है लेकिन उसे गुजरात के वाडिनार बंदरगाह पर ठहरने की इजाजत नहीं दी जा रही है। रिपोर्ट में कहा गया कि रूसी तेल टैंकर भारत के तट से 1,600 मील दूरी पर भटक रहा है। रूसी तेल जहाज एनएस सेंचुरी दक्षिण कोरिया के जरिए आ रहा था और भारत के बंदरगाह पर रुकने वाला था लेकिन अब पिछले 10 दिनों से समुद्र में ही भटक रहा है। यह जहाज उन पांच जहाजों में शामिल है जिनपर अमेरिका ने नए प्रतिबंध लगाए हैं।

भारत के नौवहन महानिदेशालय ने जानकारी दी थी कि भारत के अधिकारी फिलहाल यह निर्णय नहीं ले पा रहे हैं कि भारत में टैंकर से कच्चा तेल उतारने दिया जाए या नहीं। रूस-यूक्रेन युद्ध के बाद से रूस भारत की शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है लेकिन अमेरिकी प्रतिबंधों की सख्ती भारत के लिए मुश्किलें पैदा कर रही है। भारत पर अमेरिका के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने का भी दबाव है। माना जा रहा है कि इसी कारण रूसी टैंकर को भारतीय बंदरगाह पर उतरने की इजाजत देने में असमंजस की स्थिति बनी हुई है।

भारत अपने इस्तेमाल का 80 फीसद से ज्यादा तेल आयात करता है, ऐसे में रूसी तेल पर अमेरिकी शिकंजा भारत के लिए भी दिक्कतें पैदा कर रहा है।वेनेजुएला के रूप में भारत को एक बेहतरीन विकल्प मिल गया है जिससे अब भारत तेल की खरीद शुरू कर चुका है।

वेनेजुएला से क्यों बंद हुई थी तेल की खरीद?

साल 2019 में वेनेजुएला में निकोलस मादुरो दोबारा राष्ट्रपति चुने गए थे जिसे लेकर अमेरिका और पश्चिमी देशों ने चुनावों में धांधली का आरोप लगाया था। मादुरो के दोबारा राष्ट्रपति बनने पर अमेरिका ने वेनेजुएला पर सख्त प्रतिबंध लगा दिया और उसकी सरकारी तेल कंपनी को तेल बेचने से रोक दिया था। लेकिन अब अमेरिका ने वेनेजुएला पर लगे प्रतिबंधों में कुछ समय की ढील दे दी है। दरअसल, अगले साल वेनेजुएला में फिर से चुनाव होने हैं जिसे लेकर सरकार और विपक्ष के बीच एक समझौता हुआ है। समझौते के तहत, अगला चुनाव यूरोपीय संघ और संयुक्त राष्ट्र के अधिकारियों की निगरानी में कराया जाएगा। इस समझौते के बाद अमेरिका ने वेनेजुएला पर लगे प्रतिबंधों को अस्थायी रूप से हटा दिया है।

मूडीज ने चीन के आउटलुक को स्थिर से किया निगेटिव

नई दिल्ली। एजेंसी

रेटिंग एजेंसी मूडीज ने चीनी सरकार की क्रेडिट रेटिंग पर अपना आअटलुक स्थिर से घटाकर नकारात्मक कर दिया है। इसके लिए एजेंसी ने धीमी आर्थिक वृद्धि और रियल एस्टेट क्षेत्र में जोखिमों का हवाला दिया है। मूडीज ने कहा कि 2017 के बाद से यह चीन की सॉवरेन रेटिंग में पहली गिरावट है। अर्थव्यवस्था में नरमी और रियल एस्टेट सेक्टर में जोखिमों का हवाला देते हुए क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज ने चीन की सरकारी क्रेडिट रेटिंग पर अपना आउटलुक स्थिर से कम करके निगेटिव कर दिया है। मूडीज ने कहा कि 2017 के बाद यह पहला मौका है जब चीन की सावरेन रेटिंग को डाउनग्रेड किया गया है।

बैंको के अस्तित्व पर मंडरा रहा है खतरा

दर्जनों रियल एस्टेट डेवलपर के डिफाल्ट होने के चलते दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था 2020 से धीमी गति से प्रगति कर रही है। इस संकट के चलते चीन के कई बैंकों के सामने अपना अस्तित्व बचाना मुश्किल हो रहा है। क्रेडिट रेटिंग फर्म ने कहा कि उसे उम्मीद है कि चीन की अर्थव्यवस्था 2024 और 2025 में चार प्रतिशत की वार्षिक गति से बढ़ेगी, जो दशक के शेष सालों में 3.8 प्रतिशत तक रह जाएगी। मूडीज ने कहा कि बूढ़ी होती आबादी जैसे कारणों के चलते 2030 तक संभावित विकास में लगभग 3.5 प्रतिशत की गिरावट आएगी।

आ गई अरहर की नई फसल और इंपोर्ट भी बढ़ा

टूटने लगे थोक में दाल के दाम

नई दिल्ली। एजेंसी

दालों की महंगाई से राहत मिलनी शुरु हो गई है। कर्नाटक में अरहर की नई फसल बाजार में आने लगी है। इससे थोक मार्केट में दाल के दाम में कमी होने लगी है। इसके असर से थोक बाजार में चना और उड़द की दाल में भी गिरावट आई है। व्यापारियों का दावा है कि आने वाले दिनों में कर्नाटक के अलावा महाराष्ट्र से भी नई फसल की सप्लाई शुरू होने से प्रति किलो दाल की कीमत में 10 से 15 रुपये की गिरावट आ सकती है।

महाराष्ट्र है अरहर उत्पादन में नंबर वन

देश में सबसे ज्यादा अरहर का उत्पादन महाराष्ट्र में होता है। इसके अलावा मध्य प्रदेश, कर्नाटक में भी इसकी खेती होती है। दिसंबर और जनवरी में अरहर की नई फसल बाजार में आ जाती है। दिल्ली में दाल के एक कारोबारी ने बताया कि देश में हर साल करीब 35 से 38 लाख टन अरहर की पैदावार होती है। लेकिन पिछले साल इसमें गिरावट रही और करीब 22 लाख टन ही हुआ था। जिसकी वजह से अरहर दाल के दाम काफी बढ़ गए। स्थिति यह हो गई कि बीते चार महीने में अरहर या तुअर दाल का प्रति किलो भाव लगभग 50 रुपये की बढ़ोतरी के साथ 200 रुपये तक पहुंच गया।

शुरू हो गई नई फसल की सप्लाई

अब कनार्टक से अरहर की नई फसल की सप्लाई शुरू हो गई है। कुछ दिन बाद महाराष्ट्र से भी नई फसल की सप्लाई शुरू हो जाएगी। इससे दाम तेजी से घटेंगे। नया बाजार के दाल कारोबारी आनंद गर्ग ने बताया कि नई फसल आने से बीते 10 दिन में दाल के थोक भाव में करीब 12 रुपये की गिरावट आई है। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में 10 से 15 रुपये की गिरावट और आएगी। वर्तमान में कर्नाटक से दाल की नई फसल आने लगी है।

दालों का इंपोर्ट बढ़ा

आनंद गर्ग के मुताबिक, दाल के रेट बढ़ने के पीछे सप्लाई की कमी थी। लेकिन बीते कुछ महीने से केन्या, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, वर्मा, सूडान समेत कई देशों से अरहर और उड़द दाल की सप्लाई दोगुनी हुई है। इससे अब दाल के दाम और कम हो सकेंगे। इस बीच दालों की जमाखोरी पर लगाम कसने के लिए केंद्र सरकार ने स्टॉक लिमिट की तिथि को बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दिया है।

रिटेल में नहीं कम हो रही कीमत

थोक मंडी में दस दिन पहले अरहर दाल की कीमत में करीब 12 रुपये की गिरावट आई है, लेकिन रिटेल की दुकान पर कीमत नहीं कम हुई। एक रिटेल कारोबारी ने बताया कि अरहर की दाल 180 से 200 रुपये के रेट में बिक रही है, जबकि चने की दाल ने भी 100 रुपये का आंकड़ा छू लिया है। वहीं, थोक मंडी में अरहर दाल की कीमत 152 से 158 रुपये, चने की दाल 72 रुपये और उड़द की दाल 110 से 115 रुपये प्रति किलो है।

अर्थव्यवस्था की तूफानी तेजी के साथ आज आई एक और गुड न्यूज

GST कलेक्शन में आया बंपर उछाल, सरकार का भरा खजाना

नई दिल्ली। एजेंसी

देश की अर्थव्यवस्था तूफानी तेजी से आगे बढ़ रही है। चीन की जहां हालत खराब है। वहीं भारत लगातार तरक्की के रास्ते पर है। आज यानी शुक्रवार को एक और गुड न्यूज सामने आई है। देश के जीएसटी के कलेक्शन में जोरदार इजाफा हुआ है। वित्त मंत्रालय के द्वारा शुक्रवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक, नवंबर में जीएसटी कलेक्शन में बीते साल के समान महीने के मुकाबले 15 फीसदी के उछाल के साथ 1.68 लाख करोड़ रुपये रहा है। सरकार के लिए नवंबर 2023 का महीना शानदार साबित हुआ है। साल दर साल जीएसटी कलेक्शन में 15 फीसदी की बढ़ोतरी देखी गई है। यह लगातार नौवां महीना है जब मासिक जीएसटी कलेक्शन 1.5 लाख करोड़ रुपये से ऊपर आया है। वित्त मंत्रालय के मुताबिक नवंबर 2022 के मुकाबले नवंबर 2023 में जीएसटी कलेक्शन में 15 फीसदी का उछाल देखने को मिला है। वित्त वर्ष 2023-24 में ये छठा मौका है जब जीएसटी कलेक्शन 1.60 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा रहा है।

देश की अर्थव्यवस्था तूफानी तेजी से आगे बढ़ रही है। चीन की जहां हालत खराब है। वहीं भारत लगातार तरक्की के रास्ते पर है। आज यानी शुक्रवार को एक और गुड न्यूज सामने आई है। देश के जीएसटी के कलेक्शन में जोरदार इजाफा हुआ है। वित्त मंत्रालय के द्वारा शुक्रवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक, नवंबर में जीएसटी कलेक्शन में बीते साल के समान महीने के मुकाबले 15 फीसदी के उछाल के साथ 1.68 लाख करोड़ रुपये रहा है। सरकार के लिए नवंबर 2023 का महीना शानदार साबित हुआ है। साल दर साल जीएसटी कलेक्शन में 15 फीसदी की बढ़ोतरी देखी गई है। यह लगातार नौवां महीना है जब मासिक जीएसटी कलेक्शन 1.5 लाख करोड़ रुपये से ऊपर आया है।

वित्त मंत्रालय के मुताबिक नवंबर 2022 के मुकाबले नवंबर 2023 में जीएसटी कलेक्शन में 15 फीसदी का उछाल देखने को मिला है। वित्त वर्ष 2023-24 में ये छठा मौका है जब जीएसटी कलेक्शन 1.60 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा रहा है।

इस वजह से आई तेजी

जीएसटी कलेक्शन में आई इस तेजी के पीछे की वजह त्योहारी सीजन का होना है। नवंबर महीने में दिवाली, धनतेरस, छठ और सादियों के सीजन के चलते जीएसटी कलेक्शन में शानदार उछाल देखने को मिला है। नवंबर 2024 में जीएसटी कलेक्शन में बीते साल के समान महीने के मुकाबले 15 फीसदी के उछाल के साथ 1.68 लाख करोड़ रुपये रहा है। हालांकि अक्टूबर 2023 के मुकाबले नवंबर में जीएसटी कलेक्शन में कमी आई है। अक्टूबर महीने में जीएसटी कलेक्शन 1.72 लाख करोड़ रुपये रहा था।

जीएसटी कलेक्शन का डेटा

वित्त मंत्रालय ने जीएसटी कलेक्शन का डेटा जारी किया है जिसके मुताबिक नवंबर 2023 में जीएसटी वसूली कुल 1,67,929 करोड़ रुपये रही है जो कि इसके पहले अक्टूबर महीने में 1,72,003 करोड़ रुपये रही थी। FY24 में अब तक के जीएसटी कलेक्शन की बात करें तो सितंबर महीने में 162712 करोड़ रुपये, अगस्त महीने में 159068 करोड़ रुपये, जुलाई महीने में 165105 करोड़ रुपये, जून महीने में 161497 करोड़ रुपये, मई में 157090 करोड़ रुपये और अप्रैल में 187035 करोड़ रुपये रहा है। यह अब तक का सबसे ज्यादा है।

विप्रो ने पर्सनल केयर सेगमेंट का किया विस्तार

तीन साबुन ब्रांड को खरीदा

नई दिल्ली। एजेंसी

विप्रो को भले ही आप आईटी कंपनी के तौर पर जानते होंगे, लेकिन इसकी शुरुआत सर्फ-साबुन बेचने से ही हुई थी।आईटी के अलावा पर्सनल केयर सेक्टर में विप्रो ने अपना विस्तार शुरू कर दिया है। विप्रो ने कंज्यूमर केयर एंड लाइटिंग ने वीवीएफ (इंडिया) लिमिटेड से तीन साबुन ब्रांड जो, डोय और बैक्टर शील्ड के अधिग्रहण की घोषणा की है। इस सौदे के मूल्य का खुलासा नहीं किया गया है। यह एक ऐसा कदम है जिससे कंपनी को विस्तार करने में मदद मिलेगी। अजीम प्रेमजी की अगुवाई वाली विप्रो एंटरप्राइजेज की इकाई विप्रो कंज्यूमर केयर एंड लाइटिंग द्वारा पिछले 12 माह के भीतर यह तीसरा अधिग्रहण है। वहीं अबतक यह15वां अधिग्रहण है। कंपनी अपने खंड का विस्तार कर रही है। विप्रो कंज्यूमर की ओर से जारी बयान के अनुसार, यह अधिग्रहण विप्रो के लिए 'पर्सनल वॉश' खंड में एक रणनीतिक विस्तार होगा। इन तीनों ब्रांड का राजस्व वित्त वर्ष 2022-23 में कुल 210 करोड़ रुपये से अधिक था। विप्रो कंज्यूमर केयर एंड लाइटिंग के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) विनीत अग्रवाल ने कहा कि ये ब्रांड मौजूदा खंड के पूरक हैं और प्रमुख बाजारों में मजबूत पकड़ बनाएंगे। वीवीएफ (इंडिया) के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक रुस्तम गोदरेज जोशी ने कहा, जो, डॉय और बैक्टर शील्ड का विप्रो में विनिवेश हमारे खंड को अनुकूलित करने पर केंद्रित है। यह इन ब्रांड को विकसित करने की विप्रो की क्षमता में हमारे विश्वास को रेखांकित करता है। वीवीएफ (इंडिया) को पहले वेजिटेबल विटामिन फूड्स कंपनी के नाम से जाना जाता था।

यूरिया मैन्यूफैक्चरिंग में भी आत्मनिर्भर हो रहा है भारत

नई दिल्ली।एजेंसी

अब यूरिया खाद के लिए किसी दूसरे देश का मुंह ताकना नहीं होगा। भारत शीघ्र ही यूरिया मैन्यूफैक्चरिंग (Urea Manufacturing) में भी आत्मनिर्भर होने जा रहा है। यह जानकारी देश में रासायनिक उर्वरक बनाने वाली कंपनियों का शीर्ष संगठन फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया (FAI) ने दी है। संगठन का कहना है कि इस समय देश में 80 लाख टन यूरिया की मैन्यूफैक्चरिंग कैपिसिटी डेवलप की जा रही है। इसके दो साल के अंदर तैयार हो जाने की उम्मीद है।

क्या कहना है एफएआई का

एफएआई के अध्यक्ष सुरेश कृष्णन का कहना है कि अगले दो साल में भारत यूरिया के निर्माण में आत्मनिर्भर हो जाएगा। कृष्णन रासायनिक उर्वरक बनाने वाली कंपनी पारादीप फास्फेट लिमिटेड के मैनेजिंग डाइरेक्टर भी हैं। उन्होंने बताया कि इस समय देश में हर साल करीब 350 लाख टन यूरिया की खपत है। इसमें से करीब 285 लाख टन यूरिया का उत्पादन देश में हो जा रहा है। देश की आवश्यकता पूरी करने के लिए इस समय करीब पांच से सात मिलयन टन मतलब कि 70 लाख टन तक यूरिया का आयात करना पड़ रहा है। इससे देश के किसानों की साल भर की आवश्यकता तो पूरी हो ही जाती है, कुछ इंवेंट्री भी बची रह जाती है जो कि अगले साल काम आता है।

80 लाख टन यूरिया की फैक्ट्री बन रही है

एफएआई के अध्यक्ष ने बताया कि इस समय हर साल करीब 80 लाख टन यूरिया की प्रोडक्शन कैपिसिटी क्रिएशन कया जा रहा है। इसमें हर साल करीब 20 लाख टन यूरिया की प्रोडक्शन कैपिसिटी निजी क्षेत्र में जबकि 60 लाख टन यूरिया की प्रोडक्शन कैपिसिटी पब्लिक सेक्टर के तहत विकसित की जा रही है। ये सभी प्रोडक्शन प्लांट गैस बेस्ड हैं। इसके अगले दो साल के अंदर चालू हो जाने की उम्मीद है।

कल से हो रहा है एफएआई का सालाना सेमिनार

देश में रासायनिक उर्वरकों के निर्माण और वितरण पर चर्चा के लिए एफएआई का 59वां सालाना सेमिनार कल से नई दिल्ली में शुरू हो रहा है। तीन दिनों तक चलने वाले इस कार्यक्रम का विषय इनोवेशन इन फर्टीलाइजर एंड एग्रीकल्चर सेक्टर रखा गया है। इसका उद्घाटन केंद्रीय रसायन, उर्वरक तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया करेंगे। इस दैरान रसायन एवं उर्वरक राज्यमंत्री भगवंत खुबा भी उपस्थित रहेंगे।

अनाज उत्पादन में आत्मनिर्भर होने में खाद की प्रमुख भूमिका

दुनिया भर के कृषि वैज्ञानिकों का मानना है कि अनाज का उत्पादन बढ़ाने और भारत के इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने में रासायनिक उर्वरकों का प्रमुख योगदान है। हालांकि लोगों के मन में अभी भी रासायनिक खाद के बारे में गलत धारणा है, जिसे दूर किए जाने की आवश्यकता है। इस सेमिनार के दौरान उद्योग जगत के विशेषज्ञों के साथ किसानों का इंटरएक्शन भी कराया जाएगा। इसके एक सत्र की अध्यक्षता नीति आयोग के सदस्य प्रोफेसर रमेश चंद भी करेंगे।

दूसरे सप्ताह भी विदेशी मुद्रा भंडार में भारी बढ़ोतरी

कंगाल पाकिस्तान को भी मिली राहत

नई दिल्ली। एजेंसी

बीते सप्ताह लगातार चार दिनों तक शेयर बाजार में तेजी दिखी है। बताया जाता है कि इस समय विदेशी पोर्टफोलियो इनवेस्टर्स (FPI) भारतीय शेयर बाजार पर मेहरबान हैं। तभी तो बीते 24 नवंबर को समाप्त सप्ताह के दौरान भारत के विदेशी मुद्रा भंडार (Foreign Currency Reserve) में फिर अच्छी बढ़ोतरी हुई है। इस सप्ताह अपना विदेशी मुद्रा भंडार 2.538 अरब डॉलर बढ़ कर 597.935 अरब डॉलर पर पहुंच गया है। यह तीन महीने का उच्चतम स्तर है। इससे एक सप्ताह पहले भी अपने विदेशी मुद्रा भंडार में 5.077 अरब डॉलर से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई थी।

कहां तक पहुंच गया डॉलर का भंडार

भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से से जारी आंकड़ों के मुताबिक 24 नंवबर 2023 को समाप्त सप्ताह के दौरान अपने विदेशी मुद्रा भंडार में भारी बढ़ोतरी हुई है। इस दौरान अपना भंडार 2.538 Billion dollar बढ़ कर $597.935 Billion तक पहुंच गया है। इससे एक सप्ताह पहले भी अपना भंडार $5.077 Billion बढ़ा था। ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तो अक्टूबर 2021 में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 645 अरब डॉलर के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया था।

फॉरेन करेंसी एसेट्स में हुई बढ़ोतरी

रिजर्व बैंक की तरफ से जारी साप्ताहिक आंकड़ों के अनुसार आलोच्य सप्ताह के दौरान भारत की विदेशी मुद्रा आस्तियां (Foreign Currency Asset) बढ़ी हैं। बीते 24 नवंबर को समाप्त सप्ताह के दौरान Foreign Currency Assets (FCAs) में $2.14 Billion की बढ़ोतरी हुई है। अब अपना एफसीए भंडार USD 528.531 Billion का हो गया है। उल्लेखनीय है कि कुल विदेशी मुद्रा भंडार में विदेशी मुद्रा आस्तियां या फॉरेन करेंसी असेट (FCA) एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। डॉलर में अभिव्यक्त किये जाने वाले विदेशी मुद्रा आस्तियों में यूरो, पौंड और येन जैसे गैर अमेरिकी मुद्राओं में आई घट-बढ़ के प्रभावों को भी शामिल किया जाता है।

गोल्ड रिजर्व भी बढ़ा

बीते नवंबर महीने की 24 तारीख को समाप्त सप्ताह के दौरान भारत के स्वर्ण भंडार में भी बढ़ोतरी हुई है। इस सप्ताह Gold reserves में 296 Million डॉलर की बढ़ोतरी हुई है। अब अपना सोने का भंडार का हो गया है।

एसडीआर में हुई बढ़ोतरी

रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार, बीते सप्ताह भारत के स्पेशल ड्रॉइंग राइट या विशेष आहरण अधिकार (SDR) में बढ़ोतरी हुई है। समीक्षाधीन सप्ताह के दौरान एसडीआर 87 श्गत्त्दह डॉलर बढ़ कर 18.218 बिलियन डॉलर तक चला गया है। रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार, समीक्षाधीन सप्ताह में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के पास रखे हुए देश के मुद्रा भंडार में भी बढ़ोतरी हुई है। आलोच्य सप्ताह के दौरान इसमें USD 14 Million की बढ़ोतरी हुई है। अब यह बढ़ कर USD 4.848 Billion तक चला गया है।

पाकिस्तान में भी बढ़ा डॉलर का भंडार

पड़ोसी पाकिस्तान इस समय आर्थिक कंगाली से जूझ रहा है। विदेशी मुद्रा की हालत स्थिति ऐसी हो गई है कि इस समय वहां सिर्फ आवश्यक वस्तुओं के आयात ही हो पा रहा है। किसी फालतू सामानों के आयात पर पैसे खर्च करने पर पाबंदी है। बीते सप्ताह भारत की तरह उसके विदेशी मुद्रा भंडार में भी बढ़ोतरी हुई है, लेकिन मामूली। बीते 24 नवंबर को समाप्त सप्ताह के दौरान वहां के विदेशी मुद्रा भंडार में 90.5 मिलियन डॉलर की बढ़ोतरी हुई है। अब वहां 12.39 अरब डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार हो गया है।

जापान की कंपनी भारत में करेगी बैटरी सेल का प्रोडक्शन

चीन को झटका! देश की अर्थव्यवस्था को मिलेगा बूस्ट

नई दिल्ली। एजेंसी

कोरोना काल के बाद से भारत की अर्थव्यवथा तूफानी तेजी से आगे बढ़ रही है। पिछले दिनों विदेशी रेटिंग एजेंसियों ने भी भारत की अर्थव्यवस्था पर भरोसा जताया है। वहीं चीन की हालत खराब है। चीन में लगातार बंद हो रहे उद्योग-धंधों के बीच अर्थव्यवस्था में लगातार गिरावट देखी जा रही है। कंपनियां अब चीन के अलावा दूसरे देशों में अपना बिजनेस ले जाने की सोचने लगी हैं। विदेशी कंपनियों का भारत पर भरोसा बढ़ा है। अब देश की अर्थव्यवस्था में और तेजी देखने को मिल सकती है। बिजनेस स्टैंडर्ड की खबर के मुताबिक, जापान की कंपनी टीडीके कॉरपोरेशन भारत आ रही है। यह चीन के लिए एक और बड़ा झटका साबित हो सकता है। Apple Inc अपने ग्लोबल लिथियम आयन (Li-ion) बैटरी सेल आपूर्तिकर्ता TDK Corporation (टीडीके कॉर्पोरेशन) को भारत ला रहा है। रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि जापान की अग्रणी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स और उपकरण निर्माता देश में असेंबल किए गए आईफोन को पावर देने के लिए भारत में बैटरी सेल का निर्माण करेगी।

कंपनी को आयात करने पड़ रहे सेल

रिपोर्ट के मुताबिक, सेल की आपूर्ति एप्पल के ली-आयन बैटरी असेंबलर, सनवोडा इलेक्ट्रॉनिक्स को की जाएगी। यह पहले से ही देश में काम कर रही है और वर्तमान में दुनिया भर के विभिन्न बाजारों से सेल का आयात करती है। बता दें कि टीडीके ने साल 2005 में ली-आयन बैटरी और सेल निर्माता हांगकांग स्थित एम्पेरेक्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड का अधिग्रहण किया था। कंपनी ने हाल ही में हरियाणा में ली-आयन बैटरी के अन्य सेल बनाने को एक इकाई स्थापित करने के लिए जमीन खरीदी थी। अब इसके एप्पल को सेल की आपूर्ति के लिए कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू होने की उम्मीद है।

देश की अर्थव्यवस्था को मिलेगा बल

जापान की कंपनी के भारत में बैटरी सेल का प्रोडक्शन करने से देश की अर्थव्यवस्था को और बल मिलेगा। विदेशी रेटिंग एजेंसियों ने भी आने वाले समय में भारत की अर्थव्यवस्था पर भरोसा जताया है। देश में जिस तरह से तेजी से कंपनियां अपना कारोबार बढ़ा रही हैं, उससे आने वाले समय में युवाओं कल लिए रोजगार के नए दरवाजे खुलेंगे। वहीं देश की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगी।

AI से इन नौकरियों को है सबसे ज्यादा खतरा

रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा

नई दिल्ली। एजेंसी

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है। कई लोग ऐसे हैं जिन्हें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से भविष्य में नौकरी जाने का डर सता रहा है। अब एआई को लेकर नई रिपोर्ट सामने आई है। एक नई रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि विशेष रूप से अधिक लिपिक कार्य और वित्त, कानूनी व व्यवसाय प्रबंधन भूमिकाओं से जुड़े व्यवसाय के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) से प्रभावित होने की सबसे ज्यादा संभावना है। यूके शिक्षा विभाग द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक, प्रबंधन सलाहकारों और व्यवसाय विश्लेषकों, लेखाकारों और मनोवैज्ञानिकों के साथ शिक्षण व्यवसायों में एआई से खतरा ज्यादा बताया गया है। वहीं फाइनेंस और इंश्योरेंस सेक्टर किसी भी अन्य क्षेत्र की तुलना में एआई के संपर्क में ज्यादा हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि एआई के संपर्क में आने वाले अन्य क्षेत्र इंफॉर्मेशन-कम्यूनिकेशन, प्रोफेशनल, वैज्ञानिक, सार्वजनिक प्रशासन और रक्षा व एजुकेशन है।

बीते दिनों आई एक रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में जेनरेटिव एआई का सबसे ज्यादा असर अकाउंटिंग पर पड़ेगा। यहां 46 फीसदी काम ऐसे होते हैं जो एआई की मदद से ऑटोमैटिक तरीके से किए जा सकते हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि जेनेरिक एआई में ऑफिस टाइम को 46 फीसदी तक कम कर सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक, अकाउंटिंग के साथ अन्य नौकरियों में भी जेनेरेटिव एआई के काम के समय को कम किया जा सकता है।

अपनाई ये तकनीक

सरकारी एजेंसी ने कहा कि उसने एक ऐसी पद्धति अपनाई जिसमें 365 अलग-अलग व्यवसायों और उनके संबंधित व्यावसायिक और कार्यकर्ता विशेषताओं का विश्लेषण किया गया। इसकी तुलना 10 सबसे प्रमुख एआई एप्लिकेशन्स से की गई, जिससे यह पता लगाया जा सके कि एआई का इन क्षेत्रों में कितना प्रभाव है। शिक्षा विभाग ने कहा, 'एआई के संपर्क में आने वाले व्यवसायों में अधिक पेशेवर व्यवसाय शामिल हैं, विशेष रूप से लिपिक कार्य, फाइनेंस, कानून और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन हैं। वहीं वित्त, कानूनी पेशेवरों और यहां तक कि व्यवसाय और संबंधित सहयोगी सहायक भूमिकाओं से जुड़ी नौकरियां इस लिस्ट में क्रमश 8वें, 9वें और 10वें स्थान पर हैं।

आरबीआई की अहम बैठक शुरू, सीधा पड़ेगा आपके पैसों पर असर

नई दिल्ली। एजेंसी

भारतीय रिजर्व बैंक की मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी की बैठक आज शुरू हो गई है. रिजर्व बैंक की पॉलिसी समीक्षा बैठक 6 दिसंबर से शुरू हुई. 8 दिसंबर यानी शुक्रवार को इस बैठक में लिए गए फैसलों का एलान किया जाएगा। इस बैठक में रेपो रेट पर फैसले के साथ- साथ महंगाई देश की आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान पर फैसला लिया जाएगा, जिनका आपकी जेब पर सीधा असर होगा। रॉयटर्स की ओर से किए गए एक पोल में अनुमान लगाया गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक लगातार पांचवी बार रेपो रेट को स्थिर रख सकता है। यानी आपके लोन की ईएमआई में कोई बदलाव नहीं होगा।

आर्थिक बदहाली के बीच मूडीज ने खराब किया चीन का मूड

शेयर 5 साल के लो लेवल पर

नई दिल्ली। एजेंसी

आर्थिक मोर्चे पर कई चुनौतियों का सामना कर रहे चीन को मूडीज ने तगड़ा झटका दिया है। इस रेटिंग एजेंसी ने चीन के क्रेडिट रेटिंग आउटलुक को स्टेबल से निगेटिव कर दिया है। प्रॉपर्टी सेक्टर के संकट और इसके कारण मीडियम टर्म में इकॉनमिक ग्रोथ प्रभावित होने की आशंका के कारण ऐसा किया गया है। चीन का रियल एस्टेट सेक्टर लंबे समय से संकट से जूझ रहा है और अब इसने पूरी इकॉनमी को अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया है। आउटलुक को डाउनग्रेड किए जाने से मूडीज के चीन की क्रेडिट रेटिंग को घटाने की आशंका बढ़ गई है। चीन के वित्त मंत्रालय ने कहा कि वह देश के क्रेडिट आउटलुक को डाउनग्रेड करने के मूडीज के फैसले से निराश है। बुधवार को चीन की ब्लू-चिप कंपनियों के स्टॉक पांच साल के न्यूनतम स्तर पर पहुंच गए। साथ ही देश की करेंसी युआन भी डॉलर के मुकाबले और गिर गई।

मूडीज का कहना है कि चीन नकदी से जूझ रही स्थानीय सरकारों और सरकारी कंपनियों को आर्थिक मदद दे सकता है। इससे चीन की फिस्कल, इकनॉमिक और इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथ के लिए ब्रॉड डाउनसाइट रिस्क बढ़ गया है। रेटिंग एजेंसी ने ऐसे समय चीन के आउटलुक को डाउनग्रेड किया है जब दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकॉनमी कई तरह की आर्थिक परेशानियों का सामना कर रही है। रियल एस्टेट के दम पर चीन ने कई दशक तक तेजी से विकास किया। लेकिन पिछले दो साल से अधिक समय से यह सेक्टर गहरे संकट से जूझ रहा है।

आर्थिक मोर्चे पर कई चुनौतियों का सामना कर रहे चीन को मूडीज (Moody's) ने तगड़ा झटका दिया है। इस रेटिंग एजेंसी ने चीन के क्रेडिट रेटिंग आउटलुक को स्टेबल से निगेटिव कर दिया है। प्रॉपर्टी सेक्टर के संकट और इसके कारण मीडियम टर्म में इकॉनमिक ग्रोथ प्रभावित होने की आशंका के कारण ऐसा किया गया है। चीन का रियल एस्टेट सेक्टर लंबे समय से संकट से जूझ रहा है और अब इसने पूरी इकॉनमी को अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया है। आउटलुक को डाउनग्रेड किए जाने से मूडीज के चीन की क्रेडिट रेटिंग को घटाने की आशंका बढ़ गई है। चीन के वित्त मंत्रालय ने कहा कि वह देश के क्रेडिट आउटलुक को डाउनग्रेड करने के मूडीज के फैसले से निराश है। बुधवार को चीन की ब्लू-चिप कंपनियों के स्टॉक पांच साल के न्यूनतम स्तर पर पहुंच गए। साथ ही देश की करेंसी युआन भी डॉलर के मुकाबले और गिर गई।

मूडीज का कहना है कि चीन नकदी से जूझ रही स्थानीय सरकारों और सरकारी कंपनियों को आर्थिक मदद दे सकता है। इससे चीन की फिस्कल, इकनॉमिक और इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथ के लिए ब्रॉड डाउनसाइट रिस्क बढ़ गया है। रेटिंग एजेंसी ने ऐसे समय चीन के आउटलुक को डाउनग्रेड किया है जब दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकॉनमी कई तरह की आर्थिक परेशानियों का सामना कर रही है। रियल एस्टेट के दम पर चीन ने कई दशक तक तेजी से विकास किया। लेकिन पिछले दो साल से अधिक समय से यह सेक्टर गहरे संकट से जूझ रहा है।

रियल एस्टेट संकट

चीन के रियल सेक्टर की अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि देश की इकॉनमी में इसकी 30% हिस्सेदारी है। जानकारों का कहना है कि चीन की रियल एस्टेट संकट इतना गहरा है कि इससे उबरने में चीन को कई साल लग सकते हैं। साथ ही लोकल गवर्नमेंट का कर्ज भी चीन के लिए समस्या बन गया है। प्रॉपर्टी मार्केट में गिरावट के कारण मकानों की बिक्री में भारी गिरावट आई है। इससे सरकार का रेवेन्यू बुरी तरह प्रभावित हुआ है। कोरोना

महामारी के दौर में लॉकडाउन ने भी चीन की इकॉनमी को बुरी तरह हिलाकर रख दिया है।

माना जा रहा है कि रियल एस्टेट का संकट चीन की इकॉनमी पर भारी पड़ सकता है। इसने दूसरे सेक्टर्स को भी अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया है। खासकर तीन ट्रिलियन डॉलर की शेडो बैंकिंग इंडस्ट्री भी इससे प्रभावित होने लगी है। इसकी वजह यह है कि इस सेक्टर का रियल एस्टेट में बड़ा निवेश है। इतना ही नहीं चीन में आबादी घटने लगी है। देश का फर्टिलिटी रेट जापान से भी कम है। छह दशक में पहली बार चीन की आबादी पिछले साल घटी है।

बढ़ सकता है कर्ज

लेबर सप्लाई में गिरावट और हेल्थकेयर तथा सोशल खर्च बढ़ने से चीन का राजकोषीय घाटा और कर्ज का बोझ बढ़ सकता है। वर्कफोर्स घटने से डोमेस्टिक सेविंग्स भी घट सकती है। इस कारण इंटरेस्ट रेट बढ़ सकता है और निवेश में कमी आ सकती है। मूडीज के मुताबिक चीन की सालाना ग्रोथ रेट 2024 और 2025 में घटकर चार परसेंट पर आ सकती है। इसके बाद 2026 से 2030 तक इसके औसतन 3.8 परसेंट रहने का अनुमान है। इस साल चीन की इकॉनमी के पांच परसेंट की रफ्तार से बढ़ने की उम्मीद है। मूडीज ने चीन के सॉवरेन बॉन्ड्स के लिए लॉन्ग टर्म A1 रेटिंग बरकरार रखी है।

टाटा मोटर्स ने ऑल-न्यू इंट्रा वी70 पिकअप, इंट्रा वी20 गोल्ड पिकअप और ऐस एचटी+ लॉन्च किया

कम लागत के साथ छोटे कमर्शल वाहनों ज्यादा एफिशिएंट, फंक्शनल और उपयोगी

मुंबई। आईपीटी नेटवर्क

भारत में कमर्शल वाहनों के सबसे बड़े निर्माता टाटा मोटर्स ने ऑल-न्यू इंट्रा वी 70, इंट्रा वी20 गोल्ड और ऐस एचटीह्र को लॉन्च किया है। कंपनी ने माल या सामान को प्रभावी ढंग से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने की प्रतिबद्धता के साथ यह गाडियां पेश की हैं। इन नए वाहनों को भारी सामान कम लागत में लंबी दूरी तक पहुंचाने के लिए डिजाइन किया गया है। इन वाहनों में अपनी श्रेणी के बेहतरीन फीचर्स हैं। इन गाड़ियों का प्रयोग कई कामों के लिए किया जाता है। यह शहरों और गांवों में ट्रांसपोर्टर्स को बेहतर मुनाफा और उत्पादकता मुहैया कराती है। टाटा मोटर्स ने लोकप्रिय इंट्रा वी50 और ऐस डीजल व्हीकल्स का नया वर्जन लॉन्च किया। इसे स्वामित्व की कम लागत के साथ ईंधन की कम खपत करने के लिए फिर से बनाया गया है। नई गाडियों के लॉन्च के साथ टाटा मोटर्स ने नए कमर्शल वाहन और पिकअप की बड़ी रेंज पेश की है। इससे उपभोक्ता अपनी जरूरतों के हिसाब से आदर्श वाहन पसंद कर सकते हैं। अब देश भर में इन वाहनों की बुकिंग टाटा मोटर्स सीवी डीलरशिप पर खुल गई है।

टाटा मोटर्स के एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर श्री गिरीश वाघ ने इन वाहनों को लॉन्च करते हुए कहा, 'तरह-तरह का सामान इधर से उधर ले जाने के लिए ये वाहन आदर्श समाधान मुहैया कराते हैं। हमारे छोटे कमर्शल वाहन और पिकअप उपभोक्ताओं को उनकी कमाई का साधन मुहैया कराते हैं। इन वाहनों को अपने उपभोक्ताओं की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए जाना जाता है। आज लॉन्च की गई गाड़ियों में प्रमुख फीचर्स जोड़े गए हैं। जिन लोगों को अपने सामान को काफी प्रभावी ढंग से इधर से उधर पहुंचाने की जरूरत होती है, उनकी तरफ से इस तरह के व्हीकल्स की काफी डिमांड है। ईंधन की खपत को कम से कम रखने के लिए इन गाड़ियों को डिजाइन किया गया है। इससे लंबी दूरी तक ज्यादा माल पहुंचाया जा सकता है। तेजी से बढ़ते शहरीकरण, फलती-फूलती ई-कॉमर्स की व्यवस्था, खपत में बढ़ोतरी, एक हब पर केंद्रित माल के वितरण का मॉडल विकसित हुआ है, लेकिन अब तक माल को बेहतरीन ढंग से एक जगह तक पहुंचाने में सक्षम और प्रभावी ट्रांसपोर्टेशन को उतना महत्व नहीं दिया गया है। कंपनी का हर वाहन माल को विश्वसनीय और सुरक्षित ढंग से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए डिजाइन किया गया है। इसके साथ ही ये वाहन मालिकों के साथ व्यक्तिगत उपभोक्ताओं को बेहतर वाणिज्यिक लाभ प्रदान करते हैं। कंपनी के वाहन भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था की बुनियादी जरूरतों को पूरा करते है।'

ओला इलेक्ट्रिक ने अपने दिसंबर टू रिमेंबर अभियान की घोषणा की

इंदौर। आईपीटी नेटवर्क

भारत की सबसे बड़ी ईवी कंपनी ओला इलेक्ट्रिक ने एंड आईएस एजमिशन में तेजी लाने के लिए अपने दिसंबर टू रिमेंबर अभियान की घोषणा की। 3 दिसंबर से शुरू होने वाले इस अभियान में एकदम नया एस1 एक्सत्र अब 20,000 रुपये के फ्लैट डिस्काउंट के साथ मिल सकेगा, जिसका मतलब एस1 एक्सत्र की कीमत अब घटकर केवल 89,999 रुपये हो गई है। इस वजह से एस1 एक्सत्र सबसे सस्ते 2व्हीलर ईवी स्कूटरों में से एक बन गया है। जिसे अपनाना सबके लिए आसान हो गया है।

ओला के चीफ मार्केटिंग ऑफिसर, अंशुल खंडेलवाल ने कहा ओला इलेक्ट्रिक ने नवम्बर महीने में लगभग 30,000 इकाइयों की रिकॉर्ड-तोड़ बिक्री के साथ एक नया इंडस्ट्री बेंच मार्क स्थापित किया है। लोग ईवी बड़ी आसानी से अपना सके इस बात में तेजी लाने और ईवी को सभी के लिए जरूरी बनाने के लिए, हाजिर हैं हम अपने नए एस1 एक्सत्र के साथ, जो सारी बाधाओं को पार करने में सक्षम है। जानीमानी आईसीई स्कूटर के बराबर कीमत के साथ, हमें विश्वास है कि एस1 एक्सत्र एंड आईएस एजके लिए पूरी तरह से तैयार है। हमारे स्कूटरों की लम्बी चैड़ी रेंज और उनकी आकर्षक कीमत के साथ, मेरा यह मानना है कि ग्राहकों के पास अब आईसीई उत्पाद खरीदने का कोई बहाना नहीं होगा।

आईआईएफएल समस्ता बॉन्ड्स की मदद से 1,000 करोड़ रु. तक की पूंजी जुटाएगा

इंदौर। आईपीटी नेटवर्क

भारत की सबसे बड़ी नॉन-बैंकिंग माईक्रोफाईनेंस कंपनियों में से एक, आईआईएफएल समस्ता फाईनेंस सिक्योर्ड बॉन्ड्स के अपने पहले पब्लिक इश्यू की मदद से 1,000 करोड़ रु. तक की पूंजी जुटाएगा, जिसका उद्देश्य व्यावसायिक वृद्धि और पूंजी निर्माण के लिए किया जाएगा। ये बॉन्ड अत्यधिक सुरक्षा के साथ 10.50 प्रतिशत तक का रिटर्न प्रदान करेंगे। ये इश्यू सोमवार, 4 दिसंबर, 2023 से मिलना शुरू होंगे, और शुक्रवार, 15 दिसंबर, 2023 तक मिलेंगे। आईआईएफएल समस्ता आईआईएफएल फाईनेंस का अंग है, जो भारत के सबसे बड़े रिटेल केंद्रित एनबीएफसी समूहों में से एक है, जिसके पास 73,066 करोड़ रु. के लोन एस्सेट अंडर मैनेजमेंट हैं। आईआईएफएल समस्ता फाईनेंस के एमडी एवं सीईओ, श्री वेंकटेशएन ने कहा, "आईआईएफएल समस्ता अपनी 1,500 शाखाओं के द्वारा पूरे भारत में मजबूत स्थिति में मौजूद है। यह सेवाओं की कमी वाले और उनसे वंचित लोगों की क्रेडिट की जरूरतों को पूरा करता है, जो मुख्यतः अपने विस्तृत पोर्टफोलियो के साथ वंचित पृष्ठभूमि की महिला उद्यमियों पर केंद्रित है। इन बॉन्ड्स की मदद से एकत्रित किए गए फंड का उपयोग इन ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करने और व्यावसायिक वृद्धि लाने के लिए किया जाएगा।"

हथेली में होने वाली खुजली देती है शुभ और अशुभ संकेत

हर कोई आर्थिक और वित्तीय सुरक्षा चाहता है। कड़ी मेहनत और समर्पण के अलावा भाग्य भी बड़ी भूमिका निभाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, हथेलियों की खुजली यह संकेत देती है कि धन मिलेगा या नहीं। इस संबंध में महिलाओं और पुरुषों के हाथ अलग-अलग होते हैं। आइए जानते हैं कि हथेलियों की खुजली और धन प्राप्ति का क्या संबंध है।

डॉ. संतोष वाधवानी
रत्न एवं वास्तु विशेषज्ञ, अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिष एवं वास्तु एसोसिएशन प्रदेश प्रवक्ता

ज्योतिष और सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार, हथेलियों में खुजली होना देवी लक्ष्मी की कृपा का संकेत है। हालांकि इसमें कुछ बातें अहम है। जैसे हथेली कौन-सी है। हथेली महिला या पुरुष की है। वैदिक ज्योतिष के मुताबिक, दाहिने हाथ की हथेली पर खुलजी का मतलब है कि आपको जल्द ही धन मिलेगा। इसके अलावा जल्द ही जीवन में नया व्यक्ति जुड़ने वाला है।

पुरुषों में दाहिनी हथेली में खुजली का संकेत

पुरुषों के लिए दाहिने हथेली में खुजली होना एक अच्छा संकेत है। यह संकेत है कि व्यक्ति खोया हुआ धन या लॉटरी जीत सकता है। या किसी अन्य रचनात्मक माध्यम से पैसे मिल सकते है।

पुरुषों में बायीं हथेली में खुजली का संकेत

अगर पुरुषों के बाएं हाथ की हथेली में खुजली होती है, तो धन के मामले में भाग्य खराब हो जाएगा। या बेवजह पैसा खर्च हो सकता है। बाएं हथेली में खुजली दुर्भाग्य का संकेत है।

महिलाओं के लिए बायीं हथेली में खुजली होने का संकेत

किसी महिला का बायीं हथेली में खुजली इस बात का प्रतीक है कि वे आर्थिक रूप से सफल होंगी। यह समृद्धि की तरफ इशारा करता है।

महिलाओं के लिए दाहिनी हथेली में खुजली का संकेत

सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार, जिस महिला की दाहिनी हथेली में बार-बार खुजली होती है। उसे भविष्य में धन हानि हो सकती है। वहीं, बाएं हाथ से कभी किसी को पैसा नहीं देना चाहिए। पैसे हमेशा दाहिने हाथ से देना चाहिए। मान्यता है कि इससे किसी अन्य तरीके से धन वापस आ जाएगा।

मंगल सूर्य की युति से बनेगा आदित्य मंगल योग

इन राशि वालों के लिए शुभ रहेगा नया साल

डॉ. आर.डी. आचार्य
9009369396
ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ
इंदौर (म.प्र.)

साल 2024 के शुरू होने से पहले कई ग्रहों का शुभ संयोग बनने जा रहा है। साल 2024 के शुरूआत में कई ग्रह अपनी उच्च राशि और स्वराशि में प्रवेश करेंगे। इसके अलावा कई ग्रहों की युति भी बनेंगी। वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ग्रहों का गोचर व्यक्ति के जीवन पर काफी गहरा प्रभाव रहता है। ग्रहों के गोचर और ग्रहों की युति से कुछ लोगों को लाभ तो कुछ को चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इस बार साल 2024 के शुरू होने से पहले यानी दिसंबर माह में कई ग्रहों के संयोग से शुभ राजयोग बन रहा है। आपको बता दें कि दिसंबर 2023 में सूर्य और मंगल की युति धनु राशि में होने जा रही है। सूर्य-मंगल की युति से आदित्य मंगल योग का निर्माण होगा। आदित्य मंगल योग से कुछ राशि के जातकों को विशेष लाभ मिलने के संकेत दिखाई रहे हैं। इसके अलावा साल 2024 के शुरू होने से पहले आदित्य मंगल योग बहुत ही शुभ साबित होने वाला है।

मेष राशि

मेष राशि के जातकों के लिए आदित्य-मंगल राजयोग का निर्माण नवम भाव में हो रहा है। मेष राशि के जातकों के लिए यह योग बहुत ही शुभ साबित होने वाला है। नौकरी की तलाश करने वाला जातकों के लिए आने वाला साल बहुत ही शुभ साबित होगा। अच्छी नौकरी के प्रस्ताव प्राप्त होंगे। भाग्य का अच्छा साथ आपको मिलेगा। सभी तरह की योजनाएं अच्छी तरह से फलीभूत होंगी। साल के शुरूआत में ही आपको कोई अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है।

सिंह राशि

सिंह राशि में आदित्य मंगल राजयोग का निर्माण 5वें भाव में होने जा रहा है। यह योग आपको कार्यक्षेत्र में अच्छी उपलब्धि दिलाने में कारगर साबित होगा। साल 2024 में आपके अच्छे दिन की शुरूआत होगी। अचानक धन लाभ के अवसर बढ़ेंगे। संतान की तरफ से आपको कोई शुभ समाचार प्राप्त होंगे। जो लोग मकान या जमीन-जायदाद की खरीदारी की सोच रहे हैं उनको यह शुभ अवसर इस साल जरूर प्राप्त होगा। भाग्य का अच्छा साथ मिलने की वजह से सभी तरह के कार्यों में सफलता और धन लाभ होगा। वैवाहिक और प्रेम जीवन अच्छे से बीतेगा।

धनु राशि

धनु राशि के जातकों के लिए आदित्य मंगल राजयोग बहुत ही शुभ साबित होने जा रहा है। यह राजयोग आपकी ही राशि से लग्न भाव में बनने जा रहा है। ऐसे में आपके साहस में वृद्धि होगी। जीवन में सकारात्मक बदलाव आने शुरू हो जाएंगे। नौकरीपेशा जातकों के लिए आने वाला नया साल बहुत ही शुभ साबित होगा। नौकरी में प्रमोशन और वेतन वृद्धि के योग बन रहे हैं। कार्यक्षेत्र और समाज में आपकी प्रतिष्ठा में इजाफा देखने को मिलेगा।

भौमवती अमावस्या पर करें हनुमान जी की पूजा, धन की कमी होगी दूर

पं. राजेश वैष्णव
शनि उपासक ज्योतिष रत्न एवं वास्तु विशेषज्ञ
98272 88490

हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि का बहुत महत्व होता है। पंचांग के अनुसार, हर माह के कृष्ण पक्ष की पंद्रहवीं तिथि को अमावस्या कहा जाता है। इस बार मार्गशीर्ष माह की अमावस्या 12 दिसंबर, मंगलवार को पड़ रही है। इस अमावस्या को भौमवती अमावस्या भी कहा जाता है। आइए, जानते हैं कि इसे भौमवती अमावस्या क्यों कहा जाता है और इसका क्या महत्व है। साथ ही इस दिन कौन-से उपाय करने से लाभ मिलता है।

मार्गशीर्ष अमावस्या शुभ मुहूर्त

मार्गशीर्ष माह की अमावस्या तिथि 12 दिसंबर को सुबह 06 बजकर 24 मिनट पर शुरू होगी। यह 13 दिसंबर को सुबह 05:01 बजे समाप्त होगी। ऐसे में मार्गशीर्ष अमावस्या 12 दिसंबर, मंगलवार को मनाई जाएगी।

क्यों कहा जाता है भौमवती अमावस्या?

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, मंगलवार का दिन भगवान हनुमान और मंगल देव को समर्पित होता है। मंगल देव और हनुमान जी दोनों को भौम के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए मंगलवार को पड़ने वाली मार्गशीर्ष अमावस्या को भौमवती अमावस्या कहा जाता है।

करें हनुमान जी की पूजा

मान्यता है कि भौमवती अमावस्या के दिन हनुमान जी की पूजा करने से भक्त को जीवन में आ रही आर्थिक समस्याओं से मुक्ति मिलती है। इसके अलावा आपको कर्ज से भी मुक्ति मिल जाती है। कुंडली में मंगल को मजबूत करने के लिए भी यह अमावस्या उत्तम मानी जाती है। भौमवती अमावस्या पर गुड़, घी और लाल मसूर आदि चीजों का दान करें। इससे मंगल दोष का प्रभाव भी कम हो जाता है।

तुलसी की सूखी लकड़ी से करें ये खास उपाय, होगी मां लक्ष्मी जी की कृपा

आचार्य पं. संजय वर्मा
9826380407
ज्योतिषाचार्य एवं वास्तु विशेषज्ञ, इंदौर (म.प्र.)

हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को पवित्र पौधों में से एक माना जाता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार, जिस घर में तुलसी की पौधा होता है, तो वहां का वातावरण सकारात्मक होता है, जिससे घर में कभी भी सुख-समृद्धि की कमी नहीं होती है। घर में तुलसी का पौधा लगाकर विधिवत पूजा करने से मां लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु की आशीर्वाद प्राप्त होता है। श्री हरि विष्णु को तुलसी अति प्रिय है।

कई बार बदलते मौसम या फिर ठीक ढंग से रखरखाव न करने के कारण वह सूख जाती है। । ऐसे ही आमतौर पर जब तुलसी का पौधा सूख जाता है, तो उसे हटाकर उस गमले में नया पौधा लगा देते हैं। इसके साथ ही सूखी तुलसी के पौधे को जल में प्रवाहित कर देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सूखी तुलसी का इस्तेमाल करके भी भगवान विष्णु को प्रसन्न कर सकते हैं और मां लक्ष्मी की असीम कृपा पा सकते हैं। आइए जानते हैं सूखी तुलसी का किस तरह इस्तेमाल करना होगा शुभ...

सूखी तुलसी से करें ये उपाय

सूखी तुलसी की छोटी-छोटी 7 लकड़ियां इकट्ठी कर लें। इसके बाद उन्हें एक साथ सूत से बांध दें। इसके बाद उन्हें घी में डूबों एक दीपक में रखकर भगवान विष्णु के सामने जला सकते हैं। इससे वह अति प्रसन्न होते हैं। इस उपाय को एकादशी या फिर किसी भी मास के कृष्ण या शुक्ल पत्र की त्रयोदशी तिथि के दिन कर सकते हैं।

तुलसी की सात लकड़ियों को एक साथ लेकर सूत या फिर सफेद धागे से बांध लें। इसके बाद सप्ताह में एक बार इन्हें गंगाजल में डूबों दें और फिर पूरे घर में गंगाजल का छिड़काव कर दें। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाएंगी और घर में खुशहाली बनी रहेगी।

तुलसी की 7 छोटी-छोटी लकड़ियां लेकर फिर से इन्हें बांध लें और विधिवत पूजा करने के बाद पर्स, तिजोरी या फिर धन वाले स्थान में रख दें। ऐसा करने से मां लक्ष्मी अति प्रसन्न होती है। इसके साथ ही पैसों की तंगी का सामना नहीं करना पड़ेगा।

इन 3 राशियों पर मेहरबान रहती हैं मां लक्ष्मी, कभी नहीं होती पैसों की किल्लत, मान-सम्मान की होती है वृद्धि

सूखी तुलसी की जड़ को निकाल लें। इसके बाद इन्हें धो लें और इसे किसी साफ कपड़े में करके प्रवेश द्वार में टांग सकते हैं। ऐसा करने से मां लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होगी। घर में सकारात्मक ऊर्जा अधिक प्रवेश करेंगे।

अगर आपकी कुडंली में कोई ग्रह दोष है, तो एक लाल रंग के कपड़े में थोड़ी सी सूखी तुलसी की जड़ रख लें और इसे गले या फिर बाजू में पहन लें। ऐसा करने से आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति सही हो जाएगी।

दवा कंपनियों का ड्रैगन से मोहभंग, भारतीय फार्मा सेक्टर दिखा रहे दम

नई दिल्ली। एजेंसी

चीन की खस्ताहाल इकॉनमी का हाल अब खुलकर सामने आ गया है। चीन की आर्थिक सेहत का खुलासा होने लगा है। कभी दुनिया की फैक्ट्री कहलाने वाला चीन अब अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने की कोशिशों में जुटा है। चीन की घट रही जीडीपी उसकी मुश्किलों को बढ़ा रही है। वर्ल्ड ऑफ स्टेटिस्टिक्स ने चीन के अनुमानित जीडीपी ग्रोथ को घटाकर 5 फीसदी कर दिया है। चीन का रियल एस्टेट अब तक के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। रियल एस्टेट कंपनियां दिवालिया हो रही है। वहीं अब बैंकिंग सेक्टर तक इसकी आग पहुंच गई है। चीन अभी कोरोना संकट से संभल भी नहीं पाया था कि रहस्यमयी तरीके से फैल रहे माइक्रोप्लाज्मा निमोनिया और इन्फ्लूएंजा फ्लू ने इसकी परेशानी को बढ़ा दिया है। वहीं अब चीन का फार्मा सेक्टर भी मुश्किलों में घिरता दिख रहा है। बड़ी दवा कंपनियों का चीन से मोह भंग हो रहा है। खासकर अमेरिका के साथ चीन को दुश्मनी भारी पड़ने लगी है।

चीन से मोह भंग

दवा बनाने वाली कंपनियों का चीन से मोह भंग हो रहा है। फार्मा कंपनियां चीन पर अपनी निर्भरता को कम करने की कोशिश कर रही है। ड्रगमेकर्स चीनी कॉन्ट्रैक्टर्स पर अपनी निर्भरता को घटाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि फार्मा कंपनियों के लिए चीनी कॉन्ट्रैक्टर क्लीनिकल ट्रायल्स और प्रारंभिक चरण के निर्माण में इस्तेमाल होने वाली दवाओं का उत्पादन करते हैं। अब फार्मा कंपनियां चीनी कॉन्ट्रैक्टर पर अपनी निर्भरता को कम करने

लगी हैं। कम लागत और तेज रफ्तार के कारण चीन फार्मास्युटिकल रिसर्च और मैन्युफैक्चरिंग के लिए दवा कंपनियों का पसंदीदा जगह हुआ करता था, लेकिन चीन के सख्त रवैये और अमेरिका के साथ बढ़ते ट्रेड वॉर के बाद से फार्मा कंपनियां चीन से दूरी बढ़ाने लगी है।

भारत के लिए मौका

चीन से बढ़ती दूरी भारत के लिए अवसर से कम नहीं है। बायोटेक कंपनियां क्लिनिकल ट्रायल, रिसर्च और आउटसोर्स के लिए भारतीय मैन्युफैक्टरिंग कंपनियों के साथ काम करने पर विचार कर रही है। बायोटेक कंपनियां चीन से दूरी बनाने लगी है। डायबिटीज और मोटापे के उपचार के लिए दवा बनाने वाली फार्मा कंपनी ग्लाइसेंड थेरेप्यूटिक्स के फाउंडर आषीन निमगांवकर की माने तो ऐसे कई फैक्टर्स हैं, जिसने चीन को बायोटेक कंपनियों के लिए कम आकर्षक बना दिया है। कंपनियां चीन ते बजाए भारतीय कंपनियों के साथ काम करने में रुचि दिखा रही है। चीनी कंपनियों के मुकाबले भारतीय कंपनियों को प्राथमिकता दी जा रही है। भारतीय कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन (ण्ऊश्ध्) को प्राथमिकता मिल रही है। भारत के चार प्रमुख सीडीएमओ सिनजीन, एराजेन लाइफ साइंसेज, पीरामल फार्मा सॉल्यूशंस, साई लाइफ साइंसेज के मुताबिक उन्हें बायोटेक कंपनियों खासकर पश्चिमी फार्मा कंपनियों की ओर से अधिक इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है।

भारत में बढ़ रही दिलचस्पी

चीन में कोरोना के बाद से बिगड़े हालात के बाद से कंपनियां चीन से मुंह मोड़ रही है। कंपनियां चीन से अपना पैसा निकाल रही हैं। वहीं भारत चीन का बड़ा विकल्प बनकर उभर रहा है। चीन के बजाए भारत में विदेशी कंपनियों का निवेश बढ़ रहा है। ऐपल, फॉक्सकॉन, माइक्रॉन जैसी कंपनियों ने चीन से निवेश के बजाए भारत में निवेश बढ़ाया है। वहीं अमेरिका की दिग्गज रिटेल कंपनी वॉलमार्ट ने भी चीन को झटका दिया है। वॉलमार्ट ने कहा है कि वो अब ज्यादा से ज्यादा गुड्स भारत से इंपोर्ट कर रहा है। वॉलमार्ट ने चीन पर अपनी निर्भरता को लगातार कम कर रहा है। साल 2023 में जनवरी से अगस्त के दौरान कंपनी ने अमेरिका में किए गए इंपोर्ट्स में से एक चौथाई भारत से आयात किया है।

क्वालिटी टेस्ट में फेल हुए 50 से ज्यादा कफ सिरप

नई दिल्ली। एजेंसी

खांसी होने पर कफ सिरप पीना आम बात है। ज्यादातर सभी लोग कफ सिरप (Cough Syrup) का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप भी खांसी के दौरान कफ सिरप का इस्तेमाल करते हैं तो ये खबर आपको चिंता में डाल सकती है। कफ सिरप को लेकर लगातार खबरें सामने आती रही हैं। पिछले साल उज्बेकिस्तान (Uzbekistan) में कफ सिरप (Cough Syrups) पीने से 19 बच्चों की मौत हो गई थी। रिपोर्ट में दावा किया गया था कि यह कफ सिरप नोएडा की एक कंपनी ने बनाई थी। अब कफ सिरप को लेकर एक नई खबर सामने आई है। दरअसल देश में कफ सिरप बनाने वाली 50 से

रिपोर्ट देखकर चौंक जाएंगे आप

ज्यादा कंपनियां क्वालिटी टेस्ट में फेल हो गई हैं। ग्लोबल लेवल पर 141 बच्चों की मौत के लिए भारत निर्मित कफ सिरप को जोड़ने वाली रिपोर्ट्स के बाद कई राज्यों में किए गए लैब परीक्षणों का हवाला देते हुए एक सरकारी रिपोर्ट में ये बात कही गई है।

क्या कहती है रिपोर्ट

केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) की रिपोर्ट में कहा गया है कि अक्टूबर तक जारी की गई 2,104 परीक्षण रिपोर्ट्स में से 54 कंपनियों की 128 यानी 6% रिपोर्ट मानक गुणवत्ता (एनएसक्यू) की नहीं थीं। उदाहरण के लिए, खाद्य एवं औषधि प्रयोगशाला गुजरात ने अक्टूबर तक 385 नमूनों का विश्लेषण किया, जिनमें से 20 निर्माताओं में से 51 नमूने मानक गुणवत्ता के नहीं पाए गए। इसी तरह, सेंट्रल ड्रग्स टेस्टिंग लेबोरेटरी (सीडीटीएल) मुंबई ने 523 नमूनों का विश्लेषण किया, जिनमें से 10 फर्मों के 18 नमूने गुणवत्ता परीक्षण में विफल रहे। क्षेत्रीय औषधि परीक्षण प्रयोगशाला (आरडीटीएल) चंडीगढ़ ने 284 परीक्षण रिपोर्ट जारी कीं, और 10 फर्मों के 23 नमूने एनएसक्यू थे। भारतीय फार्माकोपिया आयोग (आईपीसी) गाजियाबाद ने 502 रिपोर्ट जारी कीं, जिनमें से नौ फर्मों में से 29 गुणवत्ता परीक्षण में विफल रहीं।

WHO ने कही थी ये बात

पिछले साल अक्टूबर में विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने कहा था कि गांबिया में करीब 70 बच्चों की मौत का संबंध भारतीय निर्माता द्वारा बनाई गई खांसी और सर्दी की सिरप से हो सकता है। इसके बाद से भारत निर्मित कफ सिरप सवालों के घेरे में आ गए हैं। इस साल मई में, भारत के औषधि महानियंत्रक (डीसीजीआई) ने राज्य औषधि नियंत्रकों से कहा था कि वे अपने राज्य के स्वामित्व वाली एनएबीएल-मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं को निर्यात उद्देश्य के लिए कफ सिरप के निर्माताओं से प्राप्त नमूनों का सर्वोच्च प्राथमिकता और मुद्दे पर विश्लेषण करने के निर्देश दें।

भारतीय नियोक्ताओं को विश्वास है कि एआई से नौकरियों में वृद्धि होगी-इनडीड

इंदौर। आईपीटी नेटवर्क

अग्रणी ग्लोबल हायरिंग और मैचिंग प्लेटफॉर्म इनडीड द्वारा किए गए एक अध्ययन में खुलासा हुआ कि कार्यस्थल पर लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रभाव को लेकर क्या सोचते हैं। इस अध्ययन में नियोक्ताओं नौकरी तलाशने वालों और एआई के बीच विकसित होते हुए संबंध के बारे में पता चला, और उनकी अपेक्षाओं एवं चिंताओं तथा नियुक्ति प्रक्रिया में एआई के मौजूदा उपयोग के बारे में जानकारी सामने आई।

सशि कुमार हेड ऑफ सेल्स इनडीड इंडिया ने कहा यह नया सर्वे एक उत्साहवर्धक खबर लाया है कि नौकरी तलाशने वाले न केवल एआई की संभावनाओं को जानते हैं, बल्कि इसकी क्षमता को लेकर उत्साहित भी हैं। इससे प्रदर्शित होता है कि नौकरी तलाशने वाले अपने करियर में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए एआई को अपनाने के लिए तैयार हैं। हालाँकि नियोक्ताओं को ऐसा ढाँचा बनाने के लिए मिलकर काम करना होगा, जो टेक्नोलॉजिकल प्रगति की ओर इसका प्रभावी उपयोग कर सके।'' इस सर्वे के मुताबिक, भारतीय नियोक्ता एआई को लेकर आशान्वित हैं। उनमें से 85 प्रतिशत से ज्यादा एआई द्वारा 1 से 5 सालों में नई नौकरियों का सृजन होने की उम्मीद कर रहे हैं। नौकरी चाहने वाले अधिकांश प्रत्याशी इसके प्रभाव को लेकर उत्साहित हैं, और 53 प्रतिशत इस बात पर सहमत हैं कि एआई से नई नौकरियों का सृजन होगा।

अब एयर इंडिया के लॉन्ज में होंगी महाराजा जैसी आलीशान सुविधाएं

सजाने-संवारने के लिए दी जिम्मेदारी

नई दिल्ली। एजेंसी

एयर इंडिया के लॉन्ज में अब आपको आने वाले दिनों में वर्ल्ड क्लास सुविधाएं मिलने वाली हैं। एयर इंडिया ने अपने लॉन्ज को सजाने संवारने के लिए हिर्श बेडनर एसोसिएट्स (HBA) को नियुक्त किया है। एचबीए एक इंटीरियर डिजाइन फर्म है। बता दें कि नई दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर टर्मिनल 4 में एयर इंडिया का लॉन्ज है। एयर इंडिया अपने लॉन्ज में यात्रियों को वर्ल्ड क्लास आलीशान फैसिलीटी उपलब्ध कराना चाहती है। इसके लिए एयर इंडिया अपने लॉन्ज को बिलकुल खास तरीके से सजाना चाहती है। एयर इंडिया के इस लॉन्ज को बनने के बाद लोग देखते ही रह जाएंगे। इसको सजाने का काम जल्द ही शुरू होने वाला है।

एयर इंडिया अपने प्रीमियम यात्रियों को बेहतर अनुभव प्रदान करना चाहती है। रिपोर्ट के मुताबिक, लॉन्ज को विश्वस्तरीय भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रतिबिंबित करने के लिए डिज़ाइन किया जाएगा। भारत की समृद्ध पाक परंपराओं के अनुरूप, लॉन्ज की पेशकश की जाएगी। एयर इंडिया के चीफ कस्टमर एक्सपीरियंस ऑफिसर राजेश डोगरा के मुताबिक, वह एयर इंडिया के मेहमानों को वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी उपलब्ध कराना चाहते हैं। इसी क्रम में एयर इंडिया ने अपने लॉन्ज को बिलकुल आलीशान इंटीरियर के साथ सजाने-संवारने की तैयारी की है। इससे आने वाले समय में यात्रियों की संख्या में भी बढ़ोतरी होगी। यह कंपनी को नई पहचान भी दिलाएंगे। एचबीए के सह-सीईओ इयान कैर के मुताबिक, 'हम एयर इंडिया के साथ साझेदारी करके सम्मानित महसूस कर रहे हैं और असाधारण सेवाएं देने के लिए समर्पित हैं। इधर टाटा समूह के स्वामित्व वाली एयर इंडिया एक्सप्रेस एयरलाइन के मैनेजमेंट और केबिन क्रू मेंबर्स आमने-सामने आ गए हैं। इसकी शिकायत मिलने पर कंपनी को श्रम मंत्रालय से कारण बताओ नोटिस मिला है। सूत्रों के मुताबिक, एयरलाइन के कई केबिन क्रू मेंबर्स रूम शेयरिंग की व्यवस्था से परेशान हैं। पहले उन्होंने इसकी शिकायत मैनेजमेंट से की थी। इसके बाद यह शिकायत श्रम मंत्रालय को दी गई है।

इनोवेटिव एल्गी-पॉवर्ड फाइबर लाने के लिए

क्लीन टेक्सटाइल इनोवेशन कंपनी एल्गीइंगरू ने बिड़ला सेलूलोज़ के साथ की साझेदारी

कपड़ा उद्योग के लिए सस्टेनेबल, बायोडिग्रेडेबल और जीरो-वेस्ट सॉल्यूशन

इंदौर। आईपीटी नेटवर्क

सस्टेनेबल कपड़ा निर्माण की दिशा में कदम बढ़ाते हुए, क्लीन टेक्सटाइल इनोवेशन में अग्रणी, एल्गीइंगरू ने मेन मेड सेल्यूलोसिक फाइबर में प्रमुख बिड़ला सेलूलोज़ के साथ मिलकर काम करना शुरू किया है। पार्टियों ने एक शानदार, एल्गी-पॉवर्ड सेल्यूलोसिक फाइबर विकसित करने और लाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जो पर्यावरण के अनुकूल है और उपयोगकर्ता को कई लाभ प्रदान करता है।

इस सहयोग पर टिप्पणी करते हुए, आदित्य बिड़ला समूह और बिड़ला सेलूलोज़ के चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर डॉ. एस्पी पटेल ने कहा, 'एल्गीइंग के साथ यह सहयोग उपभोक्ताओं को अधिक सस्टेनेबल फाइबर देने पर बिड़ला सेलूलोज़ के फोकस के साथ मेल खाता है। हम एल्गीइंग के सहयोग से इस इनोवेटिव नए सेल्युलोसिक फाइबर को विकसित करने और उसका विस्तार करने के इच्छुक हैं।'

प्रकृति का उपयोग करते हुए, यह अनोखा फाइबर टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को नई परिभाषा दे रहा है। एल्गी के कई सारे अलग अलग रंगों से बना हुआ, यह पारंपरिक रंगाई प्रक्रियाओं को समाप्त करते हुए, प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले रंगों का एक बेहतरीन पैलेट प्रदान करता है। इस इनोवेशन का उद्देश्य पारंपरिक रंगाई प्रक्रियाओं से जुड़े पर्यावरण के प्रभाव को कम करते हुए अलग अलग प्रकार के डाईलेस कपड़ों को बाजार में लाना है। प्रोडक्शन को सुव्यवस्थित करके और एल्गी की सुंदरता को अपनाकर, हम एक इनोवेटिव समाधान प्रस्तुत कर रहे हैं जो देखने में आकर्षक और पारिस्थितिक रूप से जिम्मेदार भी है।

फाइबर अतिरिक्त लाभ प्रदान करता है, जैसे टोक्सिन-फ्री प्रोडक्शन और फाइबर में जोड़े गए एल्गी में मौजूद समृद्ध पोषक तत्वों, खनिजों, एंटीऑक्सिडेंट और वनस्पति गुणों से बना हुआ है जिसने उपयोगकर्ताओं के लाभ को बढ़ाया। एल्गीइंगरू के को फाउंडर और सीईओ श्रीमती रेनाना क्रेब्स ने कहा, 'बिरला सेलूलोज़ के साथ हमारी साझेदारी कपड़ा उद्योग को डिटोक्सिफाई करने और सस्टेनेबल इनोवेशन को बढ़ावा देने के हमारे साझा मिशन में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। बिड़ला सेलूलोज़ जैसे अग्रणी खिलाडी के साथ हाथ मिलाने से हमारा प्रभाव बढ़ता है, जिससे हमें उपभोक्ताओं के लिए किफायती, बेहतर उत्पाद लाने और नए उद्योगों में शाखा लगाने की अनुमति मिलती है। साथ मिलकर, हम एक उज्जवल भविष्य के लिए रास्ता बना रहे हैं, जहां फैशन और सस्टेनेबिलिटी मूल रूप से मिलती हैं।'

बिड़ला सेलूलोज़ को कैनोपी की हॉट बटन रिपोर्ट 2023 में नंबर एक रैंकिंग

लगातार चौथे साल 'डार्क ग्रीन शर्ट' में मिली उच्चतम रेटिंग

इंदौर। आईपीटी नेटवर्क

पर्यावरण पर केंद्रित गैर-लाभकारी संस्था कैनोपी ने अपनी एनुअल हॉट बटन रिपोर्ट जारी की है, जो फैशन ब्रांडों और खुदरा विक्रेताओं को वन फाइबर सोर्सिंग के लिए मैन मेड सेल्युलोसिक फाइबर (एमएमसीएफ) के सप्लायर की जानकारी प्रदान करती है। रैंकिंग पर टिप्पणी करते हुए, ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड के मेनेजिंग डायरेक्टर और बिड़ला सेलूलोज़ के बिजनेस डायरेक्टर श्री एच के अग्रवाल ने कहा, 'यह पुरुस्कार सस्टेनेबल वुड सौर्सिंग प्रैक्टिस, फ़ॉरेस्ट कंसर्वेशन, इनोवेशन, अगली पीढ़ी के फाइबर सॉल्यूशन और पूरी वैल्यू चैन में पारदर्शी संचालन में सुधार के लिए बिड़ला सेलूलोज़ के दृढ़ समर्पण और प्रतिबद्धता के लिए काम कर रही है।' अन्य वैश्विक एमएमसीएफ उत्पादकों के साथ-साथ बिड़ला सेलूलोज़ ने भी 2030 तक कम से कम 30ऋ टेरेस्टियल इकोसिस्टमके संरक्षण के लिए जैविक विविधता पर कन्वेंशन की प्रतिबद्धता के कार्यान्वयन के लिए किए जा रहे प्रयासों का समर्थन किया है। कंपनी सर्कुलरिटी को बढ़ाने के लिए ब्रांड्स और सप्लाई चेन पार्टनर्स, इनोवेटर्स और कैनोपी, फैशन फॉर गुड और सर्कुलर फैशन पार्टनरशिप जैसे ऑर्केस्ट्रेटर्स के साथ सक्रिय रूप से सहयोग करती है। कैनोपी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर निकोल रायक्रॉफ्ट ने कहा, 'कैनोपी की 2023 हॉट बटन रिपोर्ट में शीर्ष स्थान हासिल करने के लिए आदित्य बिड़ला को हार्दिक बधाई।' 'हम एमएमसीएफ सप्लाई चैन से प्राचीन और लुप्तप्राय वनों को हटाने के लिए उनकी कड़ी मेहनत की सराहना करते हैं और अगली पीढ़ी के लिए फाइबर को बड़े पैमाने पर बाजार में लाने के लिए उनकी लगातार प्रगति से प्रोत्साहित हैं।'

एक्सॉनमोबिल ने पहली एफ4 चैंपियनशिप और इंडियन रेसिंग लीग सीजन 2 को पावर देकर भारत के मोटरस्पोर्ट्स सीन को ऊपर उठाया

इस वर्ष इंडियन रेसिंग फेस्टिवल का मुख्य आकर्षण चेन्नई के नए स्ट्रीट सर्किट में रात की रेस

बेंगलुरु। आईपीटी नेटवर्क

एक्सॉनमोबिल इस वर्ष इंडियन रेसिंग फेस्टिवल को पावर देकर भारत के तेजी से बढ़ते मोटरस्पोर्ट्स सेक्टर को ऊपर उठा रहा है, जिसमें देश में पहली बार एफ 4 इंडियन चैंपियनशिप और चेन्नई के मद्रास इंटरनेशनल सर्किट (एमआईसी) और नए फॉर्मूला रेसिंग सर्किट (एफसीआर) में आयोजित होने वाली इंडियन रेसिंग लीग (आईआरएल) का दूसरा सीजन शामिल है। यह वर्ष पहली बार भारत और दक्षिण एशिया में शहर के केंद्र में द्वीप मैदानों के आसपास स्थित एफसीआर में रात की रेस का एक रोमांचक कैलेंडर शामिल है।

यह रेसिंग प्रमोशन प्राइवेट लिमिटेड (आरपीपीएल) के साथ एक्सॉनमोबिल की लगातार दूसरे वर्ष की साझेदारी का हिस्सा है, जो देश में मोटरस्पोर्ट्स की लोकप्रियता और पहुँच को बढ़ाने और इसे सभी रेसर्स के लिए अधिक किफायती बनाने की अपनी प्रतिबद्धता से प्रेरित है।

आईआरएल के साथ साझेदारी का जश्न एमआईसी, चेन्नई में आईआरएल प्री - सीजन टेस्ट में मनाया गया। इस कार्यक्रम में ड्राइवरों ने श्दंग्त 1ऊश उत्पादों का प्रदर्शन किया, इसके अलावा श्दंग्त 1ऊश ब्रांड को पूरे स्थल पर प्रमुखता से प्रदर्शित किया गया। उत्कृष्ट इंजन प्रदर्शन – जो रेसिंग के लिए केंद्रीय है, उसके लिए असाधारण ट्रैक - रिकॉर्ड वाला श्दंग्त 1 रेसर्स को आत्मविश्वास दे रहा है।

भारत की पहली फ्रैंचाइज़ी - आधारित मोटरस्पोर्ट्स लीग, आईआरएल सीजन 2 शहर - आधारित सात टीमों को एक साथ लाती है। प्रतिस्पर्धी मोटर खेल में विशिष्ट मानक लाते हुए भारत की एकमात्र चार - पहिया रेसिंग लीग और दुनिया की पहली लिंग के प्रति तटस्थ रेसिंग चैंपियनशिप आईआरएल ने मोटर रेसिंग में पहले वर्ष से ही एक अनूठा स्थान बनाया है। रेसिंग के प्रति उत्साही लोगों के लिए प्रदान किए जाने वाले उत्साह के अलावा, आईआरएल कार मैकेनिक्स और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के छात्रों के लिए इंटर्नशिप कार्यक्रमों के माध्यम से मोटरस्पोर्ट्स के लिए प्रतिभा की एक नई पीढ़ी का पोषण भी करता है।

नाइट फ्रैंक इंडिया ने सेंट्रल वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन के साथ साझेदारी की

नई दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

अग्रणी अंतरराष्ट्रीय रियल एस्टेट कंसल्टेंसी नाइट फ्रैंक इंडिया को मध्य प्रदेश राज्य में 4 स्थानों में सेंट्रल वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन (उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारतीय सरकार के तहत एक वैधानिक निकाय) के लैंड पार्सल के विपणन के लिए एक नॉलेज पार्टनर के रूप में नियुक्त किया गया है। राज्य में भंडारण विकास लागत 130.74 करोड़ रुपये होने का अनुमान है, जबकि भंडारण विकास के लिए संचयी संभावित भूमि क्षेत्र 27.01 एकड़ होने का अनुमान है। मध्य प्रदेश में 4 स्थानों में से 3 इंदौर में हैं, जिसके लिए भंडारण विकास लागत 95.66 करोड़ रुपये होने का अनुमान है, जबकि भंडारण विकास के लिए संचयी संभावित भूमि क्षेत्र 19.75 एकड़ होने का अनुमान है।

गुलाम जिया वरिष्ठ कार्यकारी निदेशक अनुसंधान सलाहकार बुनियादी ढांचा और मूल्यांकन नाइट फ्रैंक इंडिया ने कहा देश भर में बड़े डेवलपर्स के लिए वेयरहाउसिंग संपत्तियां एक आकर्षक निवेश अवसर बन गई हैं सीडब्ल्यूसी के लैंड पार्सल रणनीतिक स्थानों पर उपलब्ध हैं जो परिसंपत्ति वर्ग के कारण प्रभावी मूल्य व्यवहार्यता प्रदान करते हैं जो अन्यथा प्रीमियम प्राइस वैल्यू पर उपलब्ध होते हैं सीडब्ल्यूसी लैंड पार्सल डेवलपर्स के लिए देश के सभी भौगोलिक क्षेत्रों में अपने वेयरहाउसिंग पोर्टफोलियो का अधिक विस्तार करने का एक शानदार अवसर खोलता है।

अमित कुमार सिंह प्रबंध निदेशक सेंट्रल वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन ने कहा परिसंपत्ति आधुनिकीकरण और मुद्रीकरण जो सिर्फ 8 स्थानों और एक सीधी किराये की प्रक्रिया के साथ शुरू हुई थी, अब 54 लैंड पार्सल को कवर करते हुए एक व्यापक पहल में विकसित हुआ है, और निकट भविष्य में और भी अधिक हो सकता है। नाइट फ्रैंक इंडिया हमारा विश्वसनीय नॉलेज पार्टनर, पीपीपी मोड के माध्यम से गोदामों के मुद्रीकरण और आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में हमें सलाह दे रहा है। हमारा उद्देश्य आधुनिकीकरण और मूल्य सृजन से परे विस्तारित हैय हम लॉजिस्टिक्स लागत को कम करने के हमारे देश के दृष्टिकोण का समर्थन करने के प्रति प्रतिबद्ध हैं। आधुनिक बुनियादी ढांचे और परिचालन दक्षता सीधे भंडारण परिसंपत्तियों के लिए लागत बचत में बदल जाती है, जो बदले में अर्थव्यवस्था को बड़े पैमाने पर मदद करेगी।

स्वामी/मुद्रक/प्रकाशक सचिन बंसल द्वारा अपनी दुनिया प्रिंटर्स, 13, प्रेस काम्पलेक्स, ए.बी. रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 18, सेक्टर-डी-2, सांवेर रोड, इंडस्ट्रीयल एरिया, जिला इंदौर (म.प्र.) से प्रकाशित। संपादक- सचिन बंसल

सूचना/चेतावनी- इंडियन प्लास्ट टाइम्स अखबार के पूरे या किसी भी भाग का उपयोग, पुनः प्रकाशन, या व्यावसायिक उपयोग बिना संपादक की अनुमति के करना वर्जित है। अखबार में छपे लेख या विज्ञापन का उद्देश्य सूचना और प्रस्तुतिकरण मात्र है। अखबार किसी भी प्रकार के लेख या विज्ञापन से किसी भी संस्थान की सिफारिश या समर्थन नहीं करता है। पाठक किसी भी व्यावसायिक गतिविधि के लिए स्वविवेक से निर्णय करें। किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र इंदौर, मप्र रहेगा।